Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 349
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
बुधवार, 24 दिसम्बर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 पुरंदर एयरपोर्ट पुणे क्षेत्र में औद्योगिक विकास ...

4 सेकुलरवाद का बहाना, वोटरों पर निशाना....

7 भारत एफआईएच विश्व रैंकिंग में आठवें ....

संक्षिप्त न्यूज

माओवादियों के गढ़ मलकानगिरी में 22 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, शांति की ओर बढ़ा ओडिशा

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाईबी खुराना की उपस्थिति में एक औपचारिक समारोह के दौरान आत्मसमर्पण हुआ। आत्मसमर्पण करने वाले जवानों ने एके-47 राइफलों और सेल्फ-लोडिंग राइफलों (एसएलआर) सहित हथियारों का जखीरा जमा कराया और ओडिशा पुलिस नक्सल आत्मसमर्पण के बैनर तले उन्हें पारंपरिक शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुराना ने कहा कि आज 22 नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण किए गए हथियारों में एके सीरीज राइफलें और इंसास राइफलें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि अन्य नक्सली भी आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्यधारा में शामिल होंगे। मैं सभी नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील करता हूं, क्योंकि सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी हैं।

यह 2025 में ओडिशा में हुआ पहला बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है और यह देश भर में नक्सल-विरोधी अभियानों में तेज़ी के बीच हुआ है। स्वाभिमान अंचल के पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा मलकानगिरी, ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर लंबे समय से माओवादियों का गढ़ रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले कैडर अब राज्य के पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मुख्यधारा समाज में एकीकरण प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, 2025 में माओवादी गतिविधियों में भारी गिरावट आई है, जिसमें पूरे भारत में 1,225 आत्मसमर्पण, 270 निष्क्रियताएँ और 680 गिरफ्तारियाँ दर्ज की गई हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ इन घटनाक्रमों को माओवादी विचारधारा के क्षरण और सरकारी पहलों में बढ़ते विश्वास के प्रमाण के रूप में देखते हैं।

बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, उम्मीदवारों का एलान होना अभी भी बाकी

मुंबई। बीएमसी चुनाव के लिए से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक अधिकतर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने उम्मीदवारों का एलान नहीं किया है। बीएमसी चुनाव बेहद अहमियत रखते हैं क्योंकि बीएमसी का 2025-26 का सालाना बजट 74 हजार करोड़ रुपये हैं और बीएमसी एशिया का सबसे बड़ा नगर निकाय है। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और चुनाव नतीजे 16 जनवरी को जारी किए जाएंगे।

गठबंधन और उम्मीदवारों का एलान होना बाकी

बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 2 जनवरी तक नामांकन वापस लेने की तारीख है। अभी तक राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का भी एलान नहीं किया है और साथ ही गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे का औपचारिक एलान

नहीं हुआ है। 227 सीटों वाली बीएमसी में अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है।

महायुति में सीटों के बंटवारे पर फंसा पेंच

सत्ताधारी महायुति गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे पर मंथन चल रहा है। इसे लेकर बीती रात सीएम फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के बीच बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा शिवसेना को 90 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हैं। वहीं अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी, इसका एलान मंगलवार को हो सकता है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की आधिकारिक भूमिका की जानकारी दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा को नवाब मलिक को लेकर आपत्ति है और साथ ही भाजपा एनसीपी को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी अभी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है और अभी तक महाविकास अघाड़ी में भी सीटों का एलान नहीं किया गया है।

भाजपा नेता नवनीत राणा ने की ये अपील

'तीन से चार बच्चे पैदा करें, ताकि भारत में धर्म

मुंबई। अभिनेत्री और भाजपा नेता नवनीत राणा ने अपने धर्म के लोगों से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका कहना है कि कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करके भारत को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राणा ने कहा कि मैं सभी हिंदुओं से अपील करती हूं कि कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करें।

राणा ने आगे कहा कि कुछ लोग खुलकर कहते हैं कि उनके चार बीवियां हैं और 19 बच्चे हैं। मैं सुझाव देती हूं कि हमें भी कम से कम तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं जानती कि वह मौलाना है या कोई और, लेकिन उसने कहा कि उसके 19 बच्चे और चार बीवियां हैं और वह 30 बच्चों का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया।

भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं- राणा

भाजपा नेता राणा ने आगे कहा कि ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करके भारत को पाकिस्तान जैसा बनाने की योजना बना रहे हैं। तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट रहें? हमें भी तीन से चार बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके साथ ही राणा ने मुंबई में होने वाले निगम चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर भी बोलीं राणा

नवनीत राणा ने मुंबई में होने वाले निगम चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे के गठबंधन के बारे में भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अब असहाय हो गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव प्रचार में बाहर कदम नहीं रखा। अगर कोई भी उद्धव के साथ जुड़ता है, उनका प्रदर्शन स्थानीय चुनावों से भी कमजोर होगा।

कांग्रेस ने सरकार पर अरावली के अस्तित्व से खिलवाड़ का लगाया आरोप, कहा- जनता को गुमराह कर रहा केंद्र

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अरावली के मुद्दे को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और सवाल किया कि वह इस पर्वतमाला को पुनः परिभाषित करने को लेकर इतनी आमादा क्यों है? पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस मामले पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के 'स्पष्टीकरण' ने और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार अरावली को नए सिरे से परिभाषित करने पर क्यों तुली है और इसका असली फायदा किसे पहुंचाया जा रहा है?

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि सरकार खनन के लिए सिर्फ 0.19इ क्षेत्र का हवाला देकर जनता को गुमराह कर रही है। उनके अनुसार सरकार ने 34 जिलों के कुल क्षेत्रफल को आधार बनाया है, जबकि गणना केवल अरावली क्षेत्र के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि नई परिभाषा (100 मीटर से ऊंचे पहाड़) से दिल्ली-एनसीआर के कई पहाड़ी इलाके सुरक्षा घेरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे भू-माफिया और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा।

भजनलाल शर्मा ने भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से की मुलाकात, विकास की योजना पर हुई चर्चा

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली में नितिन नबीन से मुलाकात की। नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजस्थान के वरिष्ठ नेता राज्य के भविष्य के लिए एक रोडमैप पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। बैठक का समापन नबीन के मार्गदर्शन में राजस्थान को विकास का केंद्र बनाने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि जनता के लिए पार्टी का दृष्टिकोण सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज नई दिल्ली में मेरी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। बैठक के दौरान हमने राजस्थान में संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्य योजनाओं और जन कल्याण कार्यों में तेजी लाने

पर विस्तृत चर्चा की। हम आपके मार्गदर्शन में राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों की पहली बैठक मंगलवार को होगी, जिसकी अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे। यह बैठक मंगलवार को रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार, बैठक में संसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन की रणनीति को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 'बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने की रणनीति को अंतिम रूप देना होगा। कार्यक्रम से संबंधित समन्वय और तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होगी।

बैठक के दौरान, भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का पार्टी के सांसदों से औपचारिक परिचय कराया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ बैठक में शामिल होंगे। सभी भाजपा सांसदों के बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।

सीएम पद की अटकलों के बीच डीके शिवकुमार का दिल्ली दौरा, बोले- राजनीति के लिए नहीं आया

बैंगलुरू। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को दिल्ली यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह यात्रा केवल सिंचाई और शहरी विकास जैसे राज्य के मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए थी और उन्होंने किसी भी राजनीतिक एजेंडे से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं यहां किसी राजनीति के लिए नहीं आया हूं; मैं केवल अपने राज्य, सिंचाई और शहरी विकास के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से मिलने आया हूं। मैं अभी अन्य राजनीतिक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने अन्य राजनीतिक मामलों पर टिप्पणी करने से परहेज किया।

यह सब मुख्यमंत्री पद के रोटेशन को लेकर चल रही अटकलों के बीच हो रहा है। सरकार के कार्यकाल का आधा समय पूरा होने के बाद ढाई साल के सत्ता-साझाकरण समझौते की अफवाहें फिर से जोर पकड़ रही हैं। शिवकुमार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड रोजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे अंत की शुरुआत बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि नई वित्तपोषण प्रणाली इस योजना को राज्यों के लिए

अव्यवहारिक बना देगी।

राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि यह अंत की शुरुआत है। महात्मा गांधी का नाम बदलकर वे इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। कौन सी राज्य सरकार 40इ देगी? भाजपा शासित राज्यों सहित कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता। यह योजना भविष्य में विफल हो जाएगी... किसी भी राज्य के लिए 40इ देना असंभव है। संसद ने 18 दिसंबर को रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी विधेयक पारित किया और 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई।

यह कानून ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक सदस्य को मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है, बशर्ते वे अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। कानून की धारा 22 के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात 60:40 होगा, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर) के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। कानून की धारा 6 राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष में कुल साठ दिनों की अवधि को अग्रिम रूप से अधिसूचित करने की अनुमति देती है, जिसमें बुवाई और कटाई के चरम कृषि मौसम शामिल हैं।

मनरेगा के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहा केंद्र, किसान मजदूर संघर्ष समिति ने लगाए आरोप

नई दिल्ली। किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को कमजोर किया जा रहा है और ग्रामीण एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने मूल उद्देश्य से भटकाया जा रहा है। पन्नू ने कहा कि 2005 में शुरू होने के बाद से एमजीएनआरईजीए एक अधिकार-आधारित कार्यक्रम के रूप में कार्य करता रहा है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किए गए हालिया परिवर्तनों ने इसकी संरचना को बदल दिया है। उन्होंने देश भर में जारी किए गए 26 करोड़ जॉब कार्डों के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला दिया, जिनमें से 12 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला है। पंजाब में 20 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 11 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला है।

पन्नू ने कहा कि देश भर में इस योजना के तहत लगभग 26 करोड़ जॉब कार्ड

जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 12 करोड़ लाभार्थियों को रोजगार मिला है। अकेले पंजाब में ही लगभग 20 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और लगभग 11 लाख श्रमिकों को एमजीएनआरईजीए के तहत काम मिल रहा है। हालांकि, यह आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एमजीएनआरईजीए की संरचना में मौलिक रूप से बदलाव किया है और इसे एक नए रूप में पेश किया है, जिससे इसके मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि 'केंद्र सरकार ने ग्राम सभाओं और पंचायतों की शक्तियां छीन ली हैं, जो पहले गांवों में विकास कार्यों का निर्णय करती थीं।

पन्नू ने आगे कहा कि एमजीएनआरईजीए की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह थी कि ग्राम सभा और पंचायतों को गांवों में किए जाने वाले विकास कार्यों की प्रकृति तय करने का अधिकार था। इनमें तालाबों की गाद निकालना, नहरें खोदना, वृक्षारोपण अभियान, सिंचाई संबंधी कार्य और मिट्टी भरने जैसे कार्य शामिल थे। पन्नू ने यह भी आरोप लगाया कि निधि अनुपात को 90:10 से बदलकर 60:40 करने से राज्यों के लिए इस योजना को जारी रखना असंभव हो गया है।

सीपीआई (एम) को रास नहीं आया मोदी के साथ प्रियंका का चाय पार्टी में शामिल होना, जॉन ब्रिटास बोले- गलत संदेश गया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के सांसद जॉन ब्रिटास ने मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेताओं के साथ चाय पार्टी में शामिल होने पर चिंता व्यक्त की। जॉन ब्रिटास ने कहा कि यह कदम जनता को गलत संदेश देता है कि भाजपा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को ध्वस्त करने के कुछ ही घंटों बाद प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पी रही हैं।

सीपीआई (एम) सांसद ने कहा कि यह कदम भारत गठबंधन की एकता के लिए हानिकारक है और उन्होंने अपनी पार्टी को इस तरह के सौहार्द का समर्थन करने से अलग कर लिया। एएनआई से बात करते हुए ब्रिटास ने कहा, 'यह हम जैसे लोगों के लिए चिंता का विषय रहा है... प्रियंका गांधी और अन्य लोगों को प्रधानमंत्री के साथ चाय पार्टी में बैठे देखना हमारे लिए अच्छा नहीं था। हम उनसे बेहतर मार्गदर्शन की उम्मीद करते थे। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर भी हम ऐसी चाय पार्टियों से दूर रहे हैं। पिछले मानसून सत्र में हम दूर रहे क्योंकि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले, जब वक्फ विधेयक को जबरदस्ती पारित किया गया था, तब भी हम दूर रहे... उन सभी मुद्दों की तुलना में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था।'

उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री के साथ चाय पीना एक तमाशा था। महात्मा गांधी के शव को बुलडोजर से गिराए जाने के कुछ ही घंटों बाद ऐसा दृश्य देखना न केवल दुखद था, बल्कि इससे देश की जनता को गलत संदेश भी गया।

सात निश्चय-3 का प्रचार प्रभावी ढंग से करे विभाग, मंत्री विजय चौधरी ने विभाग के कामों की समीक्षा की

नई दिल्ली। राज्य सरकार के सात निश्चय-3 की जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग(आईपीआरडी) हर घर तक पहुंचाएगा। विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विभागीय कामों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार-प्रसार प्रभावी ढंग से हो। साथ ही, गलत सूचनाओं और अफवाहों का तुरंत खंडन भी किया जाएगा। सूचना भवन स्थित सूचना एवं जनसंपर्क में कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों से राज्य की प्रमुख योजनाओं के प्रसार पर बल दिया।

विकसित बिहार के 15 प्रमुख थीम्स पर हो रहा काम

मंत्री चौधरी ने विभाग के विभिन्न प्रचार माध्यमों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आईपीआरडी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम), आउटडोर होर्डिंग्स, फ्लेक्स, चैट बॉट और इन्फ्लूएंसर्स के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहा है।

विभाग विशेष रूप से 15 प्रमुख थीम्स पर फोकस करेगा, जिनमें रोजगार सृजन, विधि-व्यवस्था, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, पुलिस आधुनिकीकरण, नगर विकास, औद्योगिक विकास, जलवायु परिवर्तन, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और खेल शामिल हैं। समीक्षा में बताया गया कि विभाग गलत सूचनाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करता है। प्राकृतिक आपदा, शांति-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता के फीडबैक को विभिन्न माध्यमों से संग्रहित कर सरकार तक पहुंचाया जाता है।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की मुख्य योजनाएं

विभाग के काम-काज में प्रमुखता से क्षेत्रीय प्रचार योजना, विशेष अंगीभूत योजना, जनजातीय क्षेत्र उप योजना, बिहार राज्य पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना, बिहार डायरी-कैलेंडर प्रकाशन, राज्य सूचना केंद्र संचालन, आउटडोर पब्लिसिटी और पत्रकारों का प्रमाणीकरण व कल्याण शामिल हैं।

सभी विभागों के लिए जनसंपर्क पदाधिकारी

समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य के सभी विभागों में जनसंपर्क बेहतर करने के उद्देश्य से जनसंपर्क पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये पदाधिकारी योजनाओं की सही जानकारी सक्रियता से जनता तक पहुंचा रहे हैं।

बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार को महबूबा मुफ्ती ने हिजाब से जोड़ते हुए दिया आपत्तिजनक बयान

जम्मू **(एजेंसी)**। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ हो रहे भयावह उत्पीड़न पर चिंता जताने के नाम पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने और कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, वह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि आपत्तिजनक भी है। सबसे पहले सच्चाई स्पष्ट कर लेनी चाहिए। भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कोई खोखला नारा नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है। यहां कानून का शासन है, अदालतें स्वतंत्र हैं और राज्य तंत्र जवाबदेह है। किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ अपराध होता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया मौजूद है, एफआईआर से लेकर न्यायालय तक। छिटपुट घटनाओं को लेकर पूरे देश को 'नैतिक दुविधा' में बताना, दरअसल भारत की संस्थाओं और लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

इसके उलट, बांग्लादेश की ज़मीनी तस्वीर पर आंख मूंद लेना या उसे भारत के संदर्भ से जोड़कर हल्का करना सरासर बेईमानी है। वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय लंबे समय से भय, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है। मंदिरों पर हमले, घरों की तोड़फोड़ और महिलाओं के खिलाफ लक्षित हिंसा, ये सब कोई अफवाह नहीं, बल्कि बार-बार सामने आई कठोर सच्चाइयां हैं। वहां कट्टरपंथी तत्वों का दबदबा बढ़ा है और अंतरिम सरकार की इच्छाशक्ति बार-बार सवालों के घेरे में आई है। इस पृष्ठभूमि में भारत से वहां की तुलना करना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है।

विकास के नाम पर हो रहा विनाश, अरावली पहाड़ियों के विवाद के बीच आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को अरावली पहाड़ियों के विवाद को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर भारत के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा अरावली पहाड़ियों को नष्ट करने के प्रस्तावित कदम का बचाव करना शर्मनाक है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री का अरावली पहाड़ियों के प्रस्तावित विनाश का बचाव करना शर्मनाक है! पहली बात तो, पर्दाफाश होने के बाद झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? फिर, अगर अरावली पहाड़ियों का एक छोटा सा हिस्सा भी है, तो उसे खनन के लिए क्यों खोला जा रहा है? भाजपा भारत की पारिस्थितिकी को पूरी तरह नष्ट करने पर इतनी तुली क्यों है, ठीक वैसे ही जैसे वह हमारे

सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर रही है?
पोस्ट में लिखा कि आज अरावली पहाड़ियों की बात हो रही है, कल वे पश्चिमी घाट या हिमालय को खनन के लिए खोल देंगे! अरावली पहाड़ियों की रक्षा के लिए राजस्थान के सभी लोग जिस तरह सड़कों पर उतरे हैं, उसे देखकर वाकई प्रेरणा मिलती है। सरकार को अब हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए - लेकिन यह उम्मीद मौजूदा सरकार से नहीं है! एक दिन पहले, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया था कि एनसीआर क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में हरित अरावली से संबंधित मुद्दों में काफी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार, यादव ने कहा कि 2014 में जब देश में केवल 24 रामसर स्थल थे, तब से अब यह संख्या बढ़कर 96 हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अरावली क्षेत्र के सुल्तानपुर, भिंडावास, असोला, सिलिसेरह और सांभर के रामसर स्थलों की घोषणा भाजपा सरकार के कार्यकाल में की गई थी।

शंकराचार्य स्वामी नारायणानन्द तीर्थ जी के मार्गदर्शन में कांदिवली (पूर्व) में श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ का भव्य आयोजन

प्रो दयानंद तिवारी

मुंबई। श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य संदेश को जन-जन तक पहुँचाने हेतु श्री नारायण सेवा समिति, कांदिवली (पूर्व), मुंबई की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञानयज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह पावन धार्मिक अनुष्ठान 24 दिसंबर 2025 से 01 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा।
इस सात दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन में अनन्त श्री विभूषित काशी धर्म पीठाधीश्वर, जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानन्द तीर्थ जी महाराज के पावन सान्निध्य में प्रतिदिन सायं 3.00 बजे से 6.00 बजे तक श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का भाव-विभोर रसपान करेंगे।
कार्यक्रम स्थल
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदान, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व),
मुंबई - 400101
कथा सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर 24 दिसंबर 2025 (बुधवार) को दोपहर 2.00 बजे से कांदिवली श्री विश्वकर्मा मंदिर से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।
इस आयोजन के सफल संचालन हेतु जिन गणमान्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन

प्राप्त हो रहा है, उनमें श्री हरिश्चंद्र शुक्ल, श्री प्रमोद दुबे, एड. जे. डी. सिंह, पं. राममणि मिश्र, एड. ओमप्रकाश सिंह, श्री साहब लाल मिश्र, श्री अनिल पाण्डेय सहित अनेक समाजसेवी एवं धर्मप्रेमी सम्मिलित हैं।
आयोजकों ने मुंबई के समस्त धर्मप्रेमी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे परिवार एवं इष्ट-मित्रों सहित इस दिव्य धार्मिक अनुष्ठान में सहभाग कर धर्मलाभ अर्जित करें तथा सनातन सांस्कृतिक मूल्यों से आत्मिक जुड़ाव स्थापित करें। उक्त जानकारी काशी धर्म पीठ के प्रवक्ता प्रो. दयानंद तिवारी द्वारा दी गई।

मध्य रेल्वे के सोलापुर मंडल द्वारा शहाबाद रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल्वे के सोलापुर मंडल ने 23 दिसंबर 2025 को शहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक भव्य स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन कर कर्मचारी कल्याण और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ किया। कार्यरत रेलवे कर्मचारियों, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों तथा उनके परिवारजनों को समग्र चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शिविर मंडलीय रेलवे अस्पताल, सोलापुर एवं रेलवे अस्पताल, वाडी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
दोनों अस्पतालों की समर्पित चिकित्सा टीमों द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। शिविर के अंतर्गत रैंडम ब्लड शुगर, रक्तचाप जांच एवं ईसीजी परीक्षण किए गए। चिकित्सकीय जांच के आधार पर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया तथा प्रतिभागियों को स्वास्थ्य

संबंधी मार्गदर्शन एवं निवारक देखभाल के संबंध में सलाह दी गई।
इस पहल को रेलवे लाभार्थियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को लाभ हुआ। निवारक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान तथा रेलवे परिवार के समग्र कल्याण में इस शिविर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सोलापुर मंडल के उस सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए सुलभ, विस्तारित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

पीआरएसआई और जय हिंद कॉलेज के बीच उद्योग-शिक्षा सहयोग को सशक्त करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

मुंबई। जनसंपर्क और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों को उद्योगोन्मुख शिक्षा और व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई), मुंबई चैप्टर और मुंबई के प्रतिष्ठित जय हिंद कॉलेज के बीच एक समझौता ज्ञापन (श्दळ) पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता पीआरएसआई (मुंबई चैप्टर) की अध्यक्ष सुश्री अनीता श्रीवास्तव और जय हिंद कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विजय दाभोलकर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस सहयोग के अंतर्गत पीआरएसआई, कॉलेज को विशेषज्ञ व्याख्यान, कार्यशालाएँ, सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंटरशिप तथा उद्योग से प्रत्यक्ष संवाद जैसे विभिन्न माध्यमों से सहयोग प्रदान करेगा, जिससे विद्यार्थियों को अकादमिक अध्ययन के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
इस अवसर पर पीआरएसआई के सचिव डॉ. मिलिंद आवताडे, कार्यकारी सदस्य श्रीमती जैनेट अरोले, श्रीमती नाज़िया

खान, श्री मोहित पटेल और श्री साईप्रसाद शेट्टी भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जय हिंद कॉलेज के मास कम्युनिकेशन एवं पत्रकारिता विभाग की प्रा. नाज़िया खान ने कहा कि पेशेवर संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच इस प्रकार की भागीदारी आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। इससे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल और सक्षम प्रोफेशनल्स तैयार होंगे, जो देश और समाज के लिए सकारात्मक योगदान दे सकेंगे।
पीआरएसआई देश की अग्रणी जनसंपर्क पेशेवर संस्था है और यह सहयोग कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा और वास्तविक व्यावसायिक संचार अनुभव के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
यदि आप चाहें तो मैं इसे और अधिक प्रभावशाली, संक्षिप्त, या हेडलाइन-ड्रिवन न्यूज फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूँ।

डायरेक्टर डॉ. कैलाश शिंदे ने हवा की क्वालिटी के लिए सीधे फील्ड एक्शन पर फोकस करने के निर्देश दिए

दिव्यांश
मुंबई(संवाददाता)

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू किए जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुए, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे ने निर्देश दिया कि सड़कों पर मिट्टी और धूल को कम करने और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल प्रदूषण रोकने के उपायों को और सख्ती से लागू करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन विभाग को फील्ड लेवल पर ज़्यादा एक्टिव और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
माननीय हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने नवी मुंबई में कुछ जगहों का दौरा किया था और मौसम की स्थिति का निरीक्षण करके अपनी टिप्पणियाँ दर्ज की थीं। इसके अनुसार, कमिश्नर ने निर्देश दिया कि शहर की सभी जगहों पर, जिनमें वे जगहें भी शामिल हैं, वायु और धूल प्रदूषण रोकने के उपायों को और ज़्यादा प्रभावी और तेज़ किया जाना चाहिए। सभी विभागों को अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आज ही जमा करने का निर्देश देते हुए,

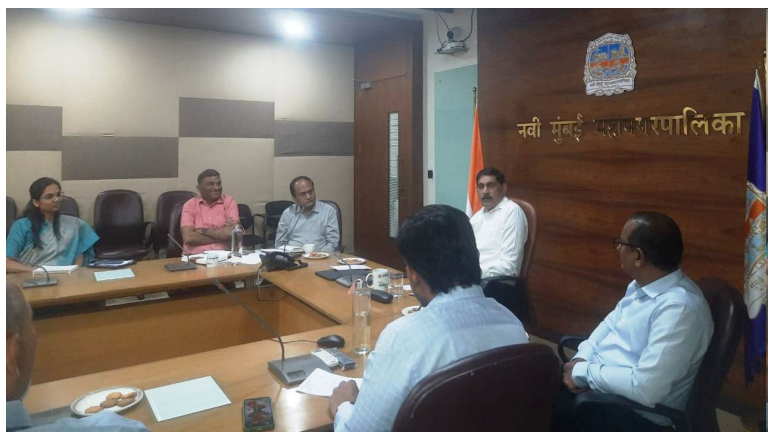

कमिश्नर ने कार्रवाई में निरंतरता बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस बैठक में सिटी इंजीनियर श्री शिरीष आर्डवाड, शहरी नियोजन के संयुक्त निदेशक श्री सोमनाथ केकान, अतिरिक्त सिटी इंजीनियर अरविंद शिंदे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के उपायुक्त डॉ. अजय गाडे, उद्यान विभाग के उपायुक्त श्री स्मिता काले के साथ-साथ सभी विभागीय अधिकारी, कार्यकारी इंजीनियर शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सीवेज निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पार्क विभागों को इस संबंध में समन्वय करना चाहिए और अपने काम के माध्यम से ठोस गतिविधि दिखानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा किए जा रहे सड़कों और अन्य कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को दूसरी जगह उड़ने से रोकने के लिए हरे जाल और काम के संकेत लगाना अनिवार्य है। इसी तरह, उन डेवलपर्स को नोटिस जारी किए गए हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं और यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा घोषित प्रदूषण रोकथाम मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। इनमें से 18 साइट्स पर कंस्ट्रक्शन भी रोक दिया गया था। कमिश्नर ने इस अवसर पर सभी साइट्स का फिर से निरीक्षण करने और मौजूदा स्थिति के बारे में उपस्थित थे।
पिछली बैठकों और निरीक्षण दौरों में सुझाए गए उपायों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने और उनमें नियमितता बनाए रखने के निर्देश देते हुए, यह स्पष्ट किया गया कि इंजीनियरिंग, जानकारी प्राप्त करने और कोई गलती पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। कमिश्नर ने यह भी सलाह दी कि प्रदूषण रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर गठित समितियों को फील्ड निरीक्षण करने पर ध्यान देना चाहिए। कमिश्नर ने यह भी सुझाव दिया कि पार्कों और मैदानों में स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी छिड़ककर मिट्टी उड़ने से रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, और मुख्य सड़कों के किनारे हरियाली बनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। कहीं भी कचरा फेंकने से रोकने के अलावा, सड़कों पर मिट्टी जमा न हो, इसके लिए पूरी तरह से सफाई जारी रखने के निर्देश दिए गए।
कमिश्नर डॉ. कैलाश शिंदे ने आज की मीटिंग में साफ़ निर्देश दिए कि नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में हवा की क्वालिटी अच्छी बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें की जानी चाहिए और ज़मीनी स्तर पर जाकर रोकथाम के उपायों और कदमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जवाहर अर्बन बैंक भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव जमा करें-सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल

मुंबई। पालघर जिला। जवाहर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती प्रक्रिया में कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण बैंक के कामकाज पर असर पड़ रहा है। इसके चलते, बैंक अधिकारियों ने एक मीटिंग में सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल से भर्ती के कुछ नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया। मंत्री पाटिल ने अधिकारियों को उसी के अनुसार प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया।
जवाहर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने एक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से जूनियर क्लर्क के 15 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। हालांकि, पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, तीन उम्मीदवारों ने नौकरी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जबकि दो अन्य उम्मीदवारों ने अंतिम रूप से चुने जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। जबकि वेटिंग लिस्ट वाले उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार मौका दिया गया, कुछ उम्मीदवारों के साथ फिर से वही हुआ। इस वजह से, फिलहाल बैंक में सिर्फ सात जूनियर क्लर्क काम कर रहे हैं। नतीजतन, बैंक ने आशंका जताई थी कि बैंक के रोज़ाना के कामकाज, ग्राहक सेवा और लोन रिकवरी पर असर पड़ेगा। इसी पृष्ठभूमि में, सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल के कार्यालय में आयोजित एक मीटिंग में, बैंक अधिकारियों ने मंत्री पाटिल से भर्ती के कुछ मानदंडों में बदलाव करने का अनुरोध किया।
मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार, खाली पदों की भर्ती के लिए हर कैडर के लिए एक अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार करना और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से अंतिम लिस्ट के अनुसार भरे जाने वाले खाली पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की 20 प्रतिशत की वेटिंग लिस्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य है। सरकारी नियमों में फिलहाल कहा गया है कि यह लिस्ट नियुक्ति के पहले आदेश से 365 दिनों तक लागू रहेगी। बैंक ने इस प्रावधान में संशोधन करने और सीमा को खाली पदों के 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का अनुरोध किया। मंत्री पाटिल ने अधिकारियों को उसी के अनुसार एक संशोधित प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया। मीटिंग में सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव संतोष पाटिल, जवाहर अर्बन बैंक के चेयरमैन आसिफ लुलानिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मुकाने, कोंकण डिवीजन के संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार भालेराव आदि मौजूद थे।

तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में संशोधन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पश्चिम रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए वन टाइम पासवर्ड के प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी टिकट बुकिंग के समय यात्री द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा तथा ओटीपी के सफल सत्यापन के पश्चात ही टिकट जारी किया जाएगा।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली पहले ही पश्चिम रेलवे से प्रारंभ होने वाली 21 ट्रेनों में लागू की जा चुकी है। अब यह ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 24 दिसम्बर, 2025 से निम्नलिखित चार और ट्रेनों में भी लागू की जा रही है:-

1. ट्रेन संख्या 14702 बांद्रा टर्मिनस - श्री गंगानगर एक्सप्रेस
2. ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस - बरौनी एक्सप्रेस
3. ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद - सहरसा एक्सप्रेस
4. ट्रेन संख्या 22956 भुज - बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस

यह नई प्रणाली कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बुकिंग के समय एक वैध एवं सुगम मोबाइल नंबर अवश्य प्रदान करें, ताकि ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह करती है।

नवी मुंबई में गीले कचरे से बनी खाद को राज्य-पंजीकृत 'हरित महासिटी कम्पोस्ट' ब्रांड दिया गया है।

नवी मुंबई नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को नई पहचान मिली

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

'हरित महासिटी कम्पोस्ट' महाराष्ट्र सरकार का एक आधिकारिक और राज्य-पंजीकृत ब्रांड है, जो शहर में पैदा होने वाले सड़ने वाले कचरे, यानी गीले कचरे और सूखे मल्च को प्रोसेस करके बनाई गई ऑर्गेनिक खाद की मार्केटिंग और बिक्री के लिए है।
महाराष्ट्र सरकार को नवी मुंबई नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट साइट पर गीले कचरे से बनी खाद की मार्केटिंग और बिक्री के लिए ग्रीन ब्रांड 'हरित महासिटी कम्पोस्ट' का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई है। इसके साथ ही, देश के सबसे स्वच्छ शहरों की 'सुपर स्वच्छ लीग' की खास कैटेगरी में शामिल नवी मुंबई शहर को नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में एक और खास रैंकिंग मिली है।
'हरित महासिटी कम्पोस्ट' ब्रांड महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने शहरी गीले कचरे से बनी ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा देने और उसकी मार्केटिंग के लिए विकसित किया है। यह ब्रांड राज्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत तय गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करता है। नवी मुंबई नगर निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट साइट पर बनी ऑर्गेनिक खाद को उसी गुणवत्ता का पाया गया है। इसलिए, नवी मुंबई नगर निगम के कचरे से बनी खाद को अब एक खास ब्रांड 'हरित महासिटी कम्पोस्ट' से पहचाना जाएगा।
यह ब्रांड बिक्री के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध कराएगा, जिससे लैंडफिल में जाने वाले कचरे में काफी कमी आएगी, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर और पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करके स्थायी कृषि को बढ़ावा मिलेगा।
इसी के तहत, नवी मुंबई नगर निगम के तुर्भे क्षेपणभूमि में सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में नगर निगम के ठोस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करके रोजाना औसतन 30 से 40 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक खाद बनाई जा रही है। इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल नवी मुंबई नगर निगम के बगीचों में किया जा रहा है। साथ ही, यह ऑर्गेनिक खाद किसानों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे किसानों को पर्यावरण के अनुकूल और गुणवत्ता वाली खाद का फायदा मिल रहा है।

मध्य रेल
भुसावल मंडल

निविदा सूचना सं. बीएसएल-एन-एसएनटी-26-2025-26 दिनांक 22.11.2025 (खुली ई-निविदा)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए, मंडल रेल प्रबंधक (सिगनल एवं दूरसंचार) मध्य रेल, भुसावल द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित ऑन लाईन खुली ई-निविदाएँ पात्र निविदाकर्ताओं से निम्न लिखित कार्य के लिए आमंत्रित की जाती है। **ई-निविदा सूचना सं.** बीएसएल-एन-एसएनटी-26-2025-26 दिनांक 22.12.2025 **कार्य का नाम:** भुसावल मंडल के मनमाड-अंकाई खंड में बीपीएसी और दोगुनी दूरी वाले सिग्नल का प्रावधान करने का कार्य। **कार्य की अनुमानित लागत:** रु. 2,74,89,743.79/- (दो करोड़ चौहत्तर लाख नवासी हजार सात सौ तैंतालीस रुपये एवं उन्यासी पैसे मात्र) **निविदा फार्म/बुकलेट की कीमत:** नहीं। **बयाना राशी:** रु. 2,87,500.00/- **कार्य पूरा करने का समय:** 09 माह एलओए देने के बाद। **निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि:** 01/01/2026 **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय:** 15/01/2026 के 15.00 बजे तक। **निविदा खुलने की तिथि और समय:** 15/01/2026 के 15.30 बजे (यदि संभव हो तो)। वेबसाइट का विवरण जहा से निविदा सूचना के बारे में पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते है। www.ireps.gov.in

मं.रे.प्र.(सि एवं दू) भुसावल 01

अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

मुख्यमंत्री ने पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों से बातचीत की

पुरंदर एयरपोर्ट पुणे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों के बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा; नौकरियों में प्राथमिकता

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। कई उद्योग पुणे में निवेश करने के इच्छुक हैं, और प्रस्तावित पुरंदर एयरपोर्ट इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह एयरपोर्ट पुणे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को काफी बढ़ावा देगा। यह सिर्फ एक यात्री एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि एक कार्गो एयरपोर्ट भी होगा, जो इसे खराब होने वाले सामानों के व्यापार के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि इस प्रोजेक्ट से पुरंदर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को बहुत फायदा होगा और इससे पुणे के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम दो प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से प्रभावित सात गांवों के निवासियों के साथ बातचीत की। पूर्व मंत्री विजय शिवतारे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अंबलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के सीईओ पी. वेलारासु, पुणे जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी और प्रभावित गांवों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकतम मुआवजा

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पुरंदर एयरपोर्ट महाराष्ट्र और पुणे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करने के बाद, एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए किसानों को अधिकतम संभव मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लेगी।

पुरंदर में प्रस्तावित एयरोसिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स से संबंधित सभी लाभ दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों के बच्चों को रोजगार में 100 प्रतिशत प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण दरों को अंतिम रूप देने के बाद, स्थानीय युवाओं के लिए उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए एक कौशल विकास केंद्र शुरू किया जाएगा।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि प्रोजेक्ट से संबंधित पहले के आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए मामले वापस ले लिए जाएंगे।

पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों और नागरिकों के उचित पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों और उनकी आने वाली पीढ़ियों को लंबे समय तक सुरक्षा देने के मकसद से, ज़मीन की असली कीमत से ज़्यादा मुआवज़े पर विचार किया जाएगा। इसलिए, राज्य सरकार ने सिर्फ़ रेडी रेकनर रेट पर निर्भर न रहने का फैसला किया है, बल्कि बातचीत के ज़रिए ज़मीन अधिग्रहण की दरें तय करने का फैसला किया है।

पहले के CIDCO प्रोजेक्ट्स में 22.5 प्रतिशत का फ़ायदा दिया गया था, और सरकार पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए इससे भी ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश कर रही है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में परिवार की बनावट का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें बड़े बच्चों के लिए अतिरिक्त जगह दी जाएगी। बहनों के हिस्से से जुड़े मुद्दों के लिए भी सही समाधान निकाले जाएंगे। छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए खास उपाय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य का पहला प्रोजेक्ट होगा जहाँ मुआवज़े के साथ-साथ वैकल्पिक ज़मीन भी दी जाएगी।

छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति और दूसरे फैसले

पुरंदर एयरपोर्ट इलाके में छत्रपति संभाजी महाराज की एक भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। पहले अधिग्रहित अतिरिक्त ज़मीन पर लगी पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी। सरकार किसानों को प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाने पर भी विचार करेगी। गाँव की बस्तियों के पुनर्वास के संबंध में उचित फैसले लिए जाएंगे।

प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को खास प्रोजेक्ट प्रभावित सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। बागवानी पेड़ों के मुआवज़े से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट से प्रभावित सभी लोगों के लिए एक अलग कॉर्पोरेशन बनाने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि 2014 के बाद राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए सभी प्रोजेक्ट सिर्फ़ राज्य के विकास और नागरिकों के हित में हैं। किसी भी किसान को भूमिहीन बनाने का कोई इरादा नहीं है। नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के अनुभव से पता चला है कि एयरपोर्ट आसपास के इलाकों में कृषि, उद्योग और व्यापार में बड़े अवसर पैदा करते हैं। इसी तरह, पुरंदर एयरपोर्ट से निश्चित रूप से क्षेत्र के किसानों और निवासियों को फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा।

इस मौके पर, पुणे के ज़िला कलेक्टर जितेंद्र डुडी ने सभा को पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अब तक की गई कार्रवाई के बारे में बताया, जबकि प्रभावित गाँवों के प्रतिनिधियों ने अपनी माँगें और ज्ञापन पेश किए।

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान को असरदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए- जयकुमार गोर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के असरदार प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम करें और ज़िला लेवल पर, खासकर ज़िला परिषदों को इस कैंपेन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोर ने निर्देश दिया है।

वे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के प्रमोशन और पब्लिसिटी के सिलसिले में मंत्रालय में एक रिव्यू मीटिंग में बोल रहे थे, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एकनाथ दावले और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में पूरे राज्य में कैंपेन को लागू करने, कैंपेन के तरीके और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर डिटेल में चर्चा हुई।

ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोर ने कहा कि मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान ग्रामीण विकास के लिहाज़ से बहुत ज़रूरी और बदलाव लाने वाला कैंपेन है और इसकी जानकारी आखिरी आदमी तक पहुंचना ज़रूरी है। ज़िला परिषदों को इस कैंपेन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और प्लान के साथ काम करना चाहिए। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर काम करेंगे, तभी कैंपेन के मनचाहे नतीजे मिलेंगे।

कैंपेन के प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए पुराने और नए मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्राम सभाओं के ज़रिए जागरूकता फैलाने, इन्फॉर्मेशन बोर्ड, पोस्टर, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक कैंपेन के मकसद, फ़ायदे और उम्मीद के मुताबिक हिस्सेदारी पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री का समृद्धि पंचायत राज अभियान सिर्फ़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहल नहीं है, बल्कि गांवों के पूरे विकास के लिए एक जन आंदोलन है। इसलिए, अगर सभी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे, तो गांव के विकास की प्रक्रिया तेज़ होगी और राज्य में पंचायत राज सिस्टम और बेहतर बनेगा, ऐसा मंत्री जयकुमार गोरे ने विश्वास जताया।

पनवेल-कलांबोली कोचिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य कार्यों से संबंधित अतिक्रमणों को हटाने के लिए विशेष पॉवर ब्लॉक संचालित किए जाएंगे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के मुंबई मंडल द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 24/25.12.2025 (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्रि) से दिनांक 30/31.12.2025 (मंगलवार/बुधवार मध्यरात्रि) तक विशेष पॉवर ब्लॉक संचालित किए जाएंगे।

पनवेल-कलंबोली कोचिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित अतिक्रमणों को हटाने का कार्य, पनवेल में प्वाइंट संख्या 10ॅ को दिवा छोर की ओर 4.5 मीटर स्थानांतरित करने के लिए शैडो ब्लॉक का निर्माण, पनवेल में प्लेटफार्म संख्या 5/6 और 7/8 के बीच एफओबी गर्डर सेटों का शुभारंभ, और पनवेल में स्टील कॉलम और क्रॉस गर्डर की स्थापना का कार्य। इस ब्लॉक में पनवेल स्टेशन की सीमा के भीतर आने-जाने वाली मेल लाइनें, लूप लाइनें, कर्जत लाइनें, इंजन रिवर्सल लाइनें और पनवेल स्टेशन के प्लेटफार्म 6 और 7 शामिल होंगे।

मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों पर निम्नलिखित प्रभाव होंगेः

ट्रेन संख्या 12134 मंगलुरु जंक्शन-सीएसएमटी एक्सप्रेस को दिनांक 24/25.12.2025 (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्रि) से दिनांक 30/31.12.2025 (मंगलवार/बुधवार मध्यरात्रि) तक प्रतिदिन आप्टा स्टेशन पर 20 से 30 मिनट के लिए रेगुलेट किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 01151 सीएसएमटी-करमाली एक्सप्रेस दिनांक 24/25.12.2025 (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्रि) से दिनांक 26/27.12.2025 (शुक्रवार/शनिवार मध्यरात्रि) तक और दिनांक 28/29.12.2025 (रविवार/सोमवार मध्यरात्रि) से दिनांक 30/31.12.2025 (मंगलवार/बुधवार मध्यरात्रि) तक प्रतिदिन कलांबोली स्टेशन पर 1 घंटे 15 मिनट के लिए रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 01151 की दिनांक 27/28.12.2025 (शनिवार/रविवार मध्यरात्रि) से शुरू होने वाली यात्रा को रिशेड्यूल करके 03:00 बजे कर दिया गया है।

ट्रेन संख्या 01152 करमाली-सीएसएमटी एक्सप्रेस दिनांक 24/25.12.2025 (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्रि) से दिनांक 30/31.12.2025 (मंगलवार/बुधवार मध्यरात्रि) तक प्रतिदिन जीते स्टेशन पर 1 घंटे 15 मिनट के लिए रेगुलेट की जाएगी ।

ट्रेन संख्या 22115 एलटीटी-करमाली एक्सप्रेस दिनांक 25.12.2025 को यात्रा आरम्भ तिथी को दिनांक 25.12.2025 को 01.45 बजे रिशेड्यूल किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 22655 एर्नाकुलम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस दिनांक 24/25.12.2025 (बुधवार/गुरुवार मध्यरात्रि) को सोमाटने स्टेशन पर 50 मिनट के लिए रेगुलेट किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 11099 एलटीटी-मडगांव एक्सप्रेस यात्रा आरम्भ की तिथी 25/26.12.2025 (गुरुवार/शुक्रवार मध्यरात्रि) को दिनांक 26.12.2025 को 01.45 बजे रिशेड्यूल किया जाएगा, यात्रा आरम्भ की तिथी 27.12.2025 को 27.12.2025 को 01.45 बजे रिशेड्यूल किया जाएगा।

दिनांक 28.12.2025 की यात्रा आरम्भ की तिथी ट्रेन का समय बदलकर दिनांक 28.12.2025 को 03:30 बजे कर दिया गया है।

ट्रेन संख्या 22114 तिरुवनंतपुरम-एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिनांक 25/26.12.2025 (गुरुवार/शुक्रवार मध्यरात्रि) को सोमाटने में 1 घंटे 15 मिनट के लिए रेगुलेट की जाएगी।

ट्रेन संख्या 22149 एर्नाकुलम-पुणे एक्सप्रेस दिनांक 26/27.12.2025 (शुक्रवार/शनिवार मध्यरात्रि) और दिनांक 30/31.12.2025 (मंगलवार/बुधवार मध्यरात्रि) को सोमाटने में 1 घंटे 15 मिनट रेगुलेट किया जाएगा ।

दिनांक 26/27.12.2025 (शुक्रवार/शनिवार मध्यरात्रि) को ट्रेन संख्या 09626 दौंड-अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मोहपे में 30 मिनट के लिए रेगुलेट की जाएगी।

दिनांक 27/28.12.2025 (शनिवार/रविवार मध्यरात्रि) को ट्रेन संख्या 22653 तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को सोमाटने में 50 मिनट के लिए रेगुलेट किया जाएगा।

दिनांक 30/31.12.2025 (मंगलवार/बुधवार मध्यरात्रि) को ट्रेन संख्या 01435 सोलापुर-एलटीटी एक्सप्रेस को मोहपे में 20 मिनट के लिए रेगुलेट किया जाएगा।

दिनांक 28/29.12.2025 (रविवार/सोमवार मध्यरात्रि) को चलने वाली ट्रेन संख्या 22193 दौंड-ग्वालियर एक्सप्रेस कर्जत-कल्याण-भिवंडी मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा और ट्रेन को पनवेल में निर्धारित ठहराव के बजाय कल्याण में ठहराव दिया जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन के संचालन में हुए परिवर्तनों पर ध्यान दें और असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन को सहयोग करें।

मनपा प्रशासन का दावा : चुनाव कराने के लिए तैयारी पूरी

मंत्र भारत। भाईंदर

मीरा-भायंदर मनपा आम चुनाव 2025-26 के परिप्रेक्ष्य में, सोमवार 23 दिसंबर, 2025 को पत्रकार प्रेस संबोधन करते हुए कमिश्नर और चीफ इलेक्शन ऑफिसर, राधाबिनोद ए. शर्मा ने पत्रकारों के उठाए गए सवालों के जवाब दिए और चुनाव प्रक्रिया के एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और लीगल पहलुओं पर जानकारी दी।कमिश्नर ने इस मौके पर साफ किया कि एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव मशीनरी मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव प्रक्रिया को बिना डरे, ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन्ड माहौल में कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मीरा-भायंदर महानगरपालिका क्षेत्र में कुल 8,19,151 वोटर हैं और उन्हें 24 वार्ड में बांटा गया है। इन वोटरों के लिए 958 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही, महानगरपालिका प्रशासन ने सभी पत्रकारों को चुनाव निर्णय अधिकारी और चुनाव से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आम चुनाव 2025-26 सूचना पुस्तिका की एक कॉपी दी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में पत्रकारों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कमिश्नर ने सभी पत्रकारों से महानगरपालिका प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे। उन्होंने 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर नागरिक से, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, आने वाले आम चुनावों में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की और वोटर की भागीदारी बढ़ाने के महत्व पर ज़ोर दिया। इस मौके पर यह उम्मीद जताई गई कि मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए लगातार काम करता रहेगा। इस मौके पर अतिरिक्त कमिश्नर डॉ. संभाजी पानपट्टे, सूचना और जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार घरत और मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद थे।

कांदिवली-बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली-बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 20/21 दिसम्बर, 2025 की रात्रि से प्रारंभ होकर 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोरीवली में अप एवं डाउन स्लो लाइनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल के कमीशनिंग कार्य हेतु 26 एवं 27 दिसम्बर, 2025 को 23:00 बजे से 07:00 बजे तक एक मेजर नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 26 दिसम्बर, 2025 को 23:00 बजे से 27 एवं 28 दिसम्बर, 2025 की मध्यरात्रि तक कांदिवली और दहीसर के बीच डाउन फास्ट लाइन पर गति प्रतिबंध भी लागू रहेगा।

इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी तथा कुछ बोरीवली/अंधेरी लोकल ट्रेनें गोरेगांव तक ही चलाई जाएंगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

परिशिष्ट-I: 26/27 दिसम्बर, 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनें।

परिशिष्ट-II: 26/27 दिसम्बर, 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनें।

परिशिष्ट-III: 27 दिसम्बर, 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनें।

नोटः उपनगरीय लोकल ट्रेनों पर पड़ने वाले प्रभाव की सूचना यथासमय दी जाएगी। 31 दिसम्बर, 2025 के लिए नववर्ष समारोह को ध्यान में रखते हुए असामान्य निरस्तीकरण न हों, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए

प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरांत 'विज्ञान रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वितरित किए गए। जाने-माने खगोल भौतिक विज्ञानी प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरांत सर्वोच्च पुरस्कार 'विज्ञान रत्न' से सम्मानित किया गया। साथ ही, महाराष्ट्र के छह वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को दो अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए।

राष्ट्रपति भवन के रिपब्लिक पवेलियन में आयोजित पुरस्कार समारोह में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और शोधकर्ताओं को चार श्रेणियों - विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम - में पुरस्कार प्रदान किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला विज्ञान रत्न पुरस्कार, जाने-माने खगोल भौतिक विज्ञानी प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया। उनकी ओर से यह पुरस्कार AYUK के निदेशक डॉ. रघुनाथन श्री आनंद ने स्वीकार किया।

नार्लीकर ने 'हॉयल-नार्लीकर सिद्धांत' विकसित किया, जिसमें एक स्थिर-अवस्था ब्रह्मांड का प्रस्ताव दिया गया जो गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ निर्माण को एकीकृत करता है। उन्होंने 'क्वासी-स्थिर अवस्था ब्रह्मांड विज्ञान' मॉडल के माध्यम से ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण और आकाशगंगाओं के निर्माण की भी व्याख्या की।

विज्ञान श्री पुरस्कार डॉ. एस. वेंकट मोहन, निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर को पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। साथ ही, न्यूट्रॉन बीमलाइन और सुपरकंडक्टिविटी (परमाणु ऊर्जा) के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डॉ. यूसुफ मोहम्मद शेख, मुंबई, के साथ- कृषि विज्ञान के लिएः डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह (ICAR - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली) - जीव विज्ञान के क्षेत्र में मानव जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से रोग संवेदनशीलता और इतिहास पर शोध के लिए, डॉ. कुमारसामी थंगराज (CSIR - CCMM, हैदराबाद), रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कम लागत वाली जल शोधन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए, प्रो. तलप्पिल प्रदीप (IIT मद्रास), प्रो. अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित (इंजीनियरिंग विज्ञान),; प्रो. महान एमजे (गणित और कंप्यूटर विज्ञान); जयन एन (अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी) को विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विज्ञान युवा श्रेणी में, विभिन्न क्षेत्रों के कई युवा शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें फिजिक्स में प्रो. अमित कुमार अग्रवाल और प्रो. सुहरिद श्रीकांत मोरे; गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्रो. सब्यसाची मुखर्जी और प्रो. श्वेता प्रेम अग्रवाल; इंजीनियरिंग विज्ञान में प्रो. अर्काप्रवा बसु; चिकित्सा विज्ञान में डॉ. सुरेश कुमार; अंतरिक्ष विज्ञान में अंकुर गर्ग; प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रो. मोहनशंकर शिवप्रकाशम, डॉ. जगदीश गुप्ता कपुगंती (कृषि विज्ञान); डॉ. सत्येंद्र कुमार मंगारौथिया (कृषि विज्ञान); देबार्का सेनगुप्ता (जैविक विज्ञान); डॉ. दीपा अगाशे (जैविक विज्ञान); डॉ. दिब्येंदु दास (रसायन विज्ञान); डॉ. वलियुर रहमान (पृथ्वी विज्ञान); प्रो. अर्काप्रवा बसु (इंजीनियरिंग विज्ञान) शामिल हैं।

अरोमा मिशन टीम को सुगंधित फसलों की अधिक उपज वाली किस्में विकसित करके किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

गुटखा और बैन चीज़ों की बिक्री होने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी- खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जिरवाल

अगर गुटखा, इसी तरह के बैन पदार्थ पाए जाते हैं, तो संबंधित इलाके के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा।

मुंबई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य में बैन गुटखा और इसी तरह की दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, विशेष सहायता मंत्री नरहरि जिरवाल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर कोई बैन पदार्थ पाया जाता है, तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री जिरवाल के निर्देशों के बाद एक सर्कुलर भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर यह पाया जाता है कि अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में बैन खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, तो उस अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसके तहत, खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्रीधर दुबे पाटिल ने भी एक सर्कुलर जारी कर सभी संभागीय संयुक्त आयुक्तों (खाद्य) को उन व्यापारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो गुपचुप तरीके से और अवैध रूप से बैन खाद्य पदार्थों को बेचते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं।

संयुक्त आयुक्त (खाद्य), सहायक आयुक्त (खाद्य) और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी बैन खाद्य पदार्थ बेचा, स्टोर या वितरित न किया जाए और बैन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, मंत्री नरहरि जिरवाल ने आदेश दिया है।

सम्पादकीय

महंगा होता जा रहा ट्रेन का सफर, सुविधाओं के लिए फिर भी परेशान रहते यात्री

भारतीय रेल को देश भर में कहीं आने-जाने के सबसे सुगम और अहम साधन के रूप में जाना जाता है। हर रोज लाखों लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए इसका सहारा लेते हैं। आए दिन सरकार गुणवत्ता के लिहाज से इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला बनाने के लिए कदम उठाने का दावा करती रहती है। मगर विचित्र यह है कि आज यात्रियों के लिए ट्रेन से सफर करना जहां एक दुस्वप्न बनता जा रहा है, वहीं सरकार जब चाहे, किराया बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करती।

हाल ही में ट्रेन में यात्री के सामान ले जाने पर वजन की सीमा लगा देने और तय वजन से ज्यादा ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क चुकाने के नियम लागू होने की खबर आई थी। अब भारतीय रेलवे ने छब्बीस दिसंबर से यात्री किराए में भी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसके तहत अब दो सौ पंद्रह किलोमीटर से ज्यादा के सफर के लिए किराया एक से दो पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। देखने में यह छोटी बढ़ोतरी लगती है, लेकिन इस इजाफे से सिर्फ अगले करीब तीन महीने में ही सरकार को लगभग छह सौ करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी आय बढ़ाने के लिए सरकार कितनी सजग है। मगर शायद इस बात का ध्यान रखना कभी जरूरी नहीं समझा जाता कि इस तरह किराया बढ़ाने का औचित्य तभी साबित हो सकता है जब यात्रियों के लिए यह असुविधाजनक न हो। यह कोई छिपी हकीकत नहीं है कि पिछले कुछ समय से ट्रेन में सफर करना कई बार कितना त्रासद साबित हो रहा है। एक से दूसरे शहर या अपने घर जाने वाले लोग अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आरक्षित टिकट मिलना आसान नहीं रह गया है।

अगर किसी व्यक्ति को हफ्ते या एक महीने पहले आरक्षित टिकट मिल जाए, तो उसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। बहुत ज्यादा सुविधाओं वाली कुछ महंगी ट्रेनों के बरक्स साधारण डिब्बों में सफर की मुश्किल की कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां लोग निर्जीव सामान की तरह किसी तरह मरते-जीते जाते हैं। इसके अलावा, ट्रेन में सामान की चोरी से लेकर लूटपाट जैसी घटनाओं पर लगाम लगा पाना आज भी एक चुनौती है।

फिर पिछले कुछ समय के दौरान ट्रेनों के पटरी से उतरने से लेकर अन्य स्वरूप में जिस तरह के हादसे हुए हैं, वे बताते हैं कि भारतीय रेल से कहीं जाना कितना सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि अलग-अलग मद में पैसा बढ़ाने के लिए बजट या किसी औपचारिक मौके का इंतजार करने की परंपरा खत्म हो गई है और सरकार अपनी सुविधा के अनुसार जब जी चाहे, नया किराया तय कर देती है।

दूसरी ओर, ट्रेनों की भारी कमी और यात्रियों को ले जाने की सीमा की वजह से रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ बताती है कि ट्रेन से सफर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के सरकारी दावे की असलियत क्या है। विडंबना यह है कि अपनी सामान्य या नियमित आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी के लिए ट्रेन का किराया बढ़ाने या अन्य प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीकों के जरिए यात्रियों से ज्यादा पैसा वसूलने को लेकर अति-सक्रिय रहने वाली सरकार की नजर में यात्री सुविधाएं कोई प्राथमिक सवाल नहीं हैं।

उसके लिए यह भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि ज्यादा किराया चुकाने का बोझ उठाने वाले बहुत सारे आम लोगों की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। क्या यह एक अफसोसनाक तस्वीर नहीं है।

सेकुलरवाद का बहाना, वोटरों पर निशाना

बिहार में जाति-धर्म की सियासी पिच पर बुरी तरह मात खाने के बावजूद इंडिया गठबंधन का भरोसा इसी पर है। तमिलनाडु में जिस तरह कार्तिगई दीपम परंपरा स्थापित करने का आदेश देने वाले मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी आर स्वामीनाथन के खिलाफ गठबंधन ने लामबंदी की है, उससे यही संकेत मिल रहे हैं। डीएमके सांसद कनिमोई की अगुआई में विपक्षी गठबंधन के 120 सांसदों द्वारा स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गठबंधन की पारंपरिक राजनीति का ही विस्तार है। विपक्षी गठबंधन यह पचा नहीं पा रहा है कि कथित सेकुलर देश में किसी जज ने बहुसंख्यक सनातनी परंपरा स्थापित करने का निर्णय दे दिया है। स्वामीनाथन के फैसले के अनुसार, जहां कार्तिदीपम मनाया जाना है, वहां एक दरगाह भी है। दरगाह और मंदिर साथ हो तो मंदिर की कीमत पर दरगाह की परंपराएं अपने यहां चलती रही हैं। अब तक की शासन व्यवस्था के लिहाज से ऐसे मामलों में मंदिर के पक्ष में फैसला सवालों के घेरे में आता है।

स्वामीनाथन ने मदुरै जिले की थिरूपरनकुंद्रम की पहाड़ी की चोटी पर कार्तिगई दीपम की परंपरा को स्थापित करने की मंजूरी दी है, जिसे 1920 के एक विवाद के बंद कर दिया गया था। यह बात और है कि डीएमके की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने विवाद की आशंका के बहाने अदालत के फैसले को लागू ही नहीं होने दिया। दिलचस्प है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसका विरोध भी नहीं किया, बल्कि सरकार ही खुद आगे बढ़कर विवाद की आशंका से भर उठी। राज्य सरकार ने स्वामीनाथन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। लेकिन इस फैसले के लिए स्वामीनाथन को पचा नहीं पा रही है। उसे लगता है कि अगर उसने जज को सबक नहीं सिखाया तो उसकी सेकुलरवाद के बुनियाद पर टिकी राजनीति में दरार पड़ सकती

है। जज को सबक सिखाने और न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के डीएमके के इस कदम में सबसे हैरतनाक कदम है, अखिलेश यादव का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पेश करते वक्त कनिमोई के साथ कांग्रेसी नेताओं और अखिलेश की मौजूदगी के संकेत गहरे हैं। दरअसल महागठबंधन के दल अल्पसंख्यक समुदाय को यह संकेत देने की कोशिश में हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन ही उसके हितों के लिए किसी जज को भी सूली पर चढ़ा सकता है। महागठबंधन की कोशिश कुछ महीने बाद होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की करीब छह फीसद अल्पसंख्यक आबादी को लुभाना भी है। वैसे देखा जाए तो राज्य की सात करोड़ 21 लाख की आबादी में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या महज 42 लाख तीस हजार ही है। ब्राह्मणवाद की बुनियाद पर उभरी डीएमके की राजनीति में अल्पसंख्यकवाद पिछड़ी जातियों को लुभाने का भी मंत्र रहा है। राज्य की अधिसंख्य पिछड़ी आबादी को भी लुभाने की इस बहाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए कार्तिगई दीपम की परंपरा को रोकने में डीएमके को कोई हिचक नहीं हुई।

इस पूरे मसले पर चर्चा से पहले जानना जरूरी है कि कार्तिगई दीपम त्योहार है क्या? दक्षिम के दीप पर्व के रूप में विख्यात कार्तिगई दीपम भगवान मुरूगन के सम्मान में तमिल महीने में दीप जलाने की परंपरा है। शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय तमिलनाडु में मुरूगन और सुब्रह्मण्यम के नाम से भी जाने जाते हैं। मदुरै जिले की जिस थिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम मनाने का आदेश अदालत ने दिया, वह भगवान मुरूगन की छह पवित्र जगहों में से एक है। मान्यता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शिवजी स्वयं अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसी दीप स्तंभ की स्मृति स्वरूप उचिपिल्लायर मंदिर के पास प्राचीन दीपाथुन नामक स्तंभ के नजदीक महादीपक जलाया जाता है। थिरूपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर भी इसकी परंपरा रही। लेकिन बाद में वहां मंदिर के नजदीक ही एक दरगाह स्थापित हो गई। दरगाह के बाद सेकुलरवाद को बढ़ावा देना जरूरी था, लिहाजा दीपम की परंपरा अधिकारियों ने रोक दी। जिसे शुरू करने को लेकर अदालती हस्तक्षेप की मांग की गई। पहले मदुरै की जिला अदालत में मामला चला और बाद में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद पहाड़ी पर तीन दिसंबर को दीप जलाने श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने लगा। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। राज्य की स्टालिन सरकार का कहना था कि इससे खून-खराबा हो सकता है। जबकि अल्पसंख्यकों की ओर से ऐसी कोई कोशिश या बयानबाजी भी नहीं हुई थी। बहरहाल, डीएमके सरकार के इस फैसले ने राज्य में पैर जमाने की कोशिश में बैठी बीजेपी को मुद्दा दे दिया। पार्टी का कहना है कि डीएमके सेक्युलरिज्म की बात करती तो है, लेकिन उसके निशाने पर सिर्फ़ हिंदू समुदाय ही रहता है। बीजेपी का आरोप है कि डीएमके ने कभी किसी गैर हिंदू परंपरा, दरगाह या आदि पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर राज्य के हिंदुओं ने कौन सी गलती की है कि उन्हें दीप जलाने के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

डीएमके की पूर्ववर्ती जस्टिस पार्टी की स्थापना 1916 में हुई थी। उसका घोषित उद्देश्य एनी बेसेंट की अगुआई वाले होम रूल लीग आंदोलन का विरोध था। जस्टिस पार्टी का मानना था कि अगर होमरूल आंदोलन सफल हुआ तो तमिलनाडु में जारी ब्राह्मणवाद की वजह से ब्राह्मण अधिकारियों की तादाद बढ़ जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जस्टिस पार्टी की स्थापना ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए हुई थी। कालांतर में उसकी ब्राह्मणवाद विरोध की राजनीति बढ़ते-बढ़ते ब्राह्मण विरोध पर केंद्रित हो गई। बाद में उसके विरोध के दायरे में हिंदी और पूरी सनातन परंपरा समा गई। यही वजह है कि स्टालिन कुनबे को हिंदुत्व की कटु आलोचना से कभी परहेज नहीं रहता। अहर्निश हिंदी विरोध और अब कार्तिगई दीपम का विरोध इसी परंपरा का विस्तार है।

विपक्षी गठबंधन को इन दिनों संविधान बचाने की बहुत चिंता है। 'संविधान खतरे में है' की आवाज बुलंद करने वाले विपक्षी गठबंधन के दलों की नजर में न्याय वही है, जो उनके नैरेटिव के हिसाब से हो, अन्यथा वह सेकुलरवाद का विरोध है। राममंदिर पर सर्वोच्च न्यायाल के फैसले को ये दल अब भी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावी कदाचार के आरोप में रायबरेली का निर्वाचन खारिज कर दिया था, तब न्यायपालिका की शक्तियां ही क्षीण कर दी गईं। मोहन कुमार मंगलम तो इससे भी दो कदम आगे बढ़ते हुए प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात करने लगे थे।

पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर यादव के एक बयान को लेकर भी विपक्षी गठबंधन नाराज हो गया था। शेखर ने कहा था, 'ये कहने में बिल्कुल गुरेज़ नहीं है कि ये हिन्दुस्तान है। यहां रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। यही क़ानून है। आप यह भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। क़ानून तो बहुसंख्यक से ही चलता है।'

इसी अंदाज में स्वामीनाथन पर भी निशाना साधा जा रहा है। इसने एक बार फिर डीएमके और इंडिया गठबंधन की सियासी रणनीति का चेहरा उजागर किया है। डीएमके ने सेक्युलरिज्म आधारित जो प्रशासनिक मॉडल बनाया है, उसके निशाने पर सिर्फ हिंदू हैं। भगवान मुरुगन की सदियों पुरानी परंपरा को रोकना उसी मॉडल की परिणति है। डीएमके की नीति अल्पसंख्यक समुदायों को खुश करना और हिंदू समुदाय के खिलाफ़ आक्रामक रहा है। राज्य में वक्फ की ज़मीनों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। चर्च का धन भी अछूता है। लेकिन हिंदू मंदिरों के कोष पर राज्य का नियंत्रण है। मंदिरों की जमीनें भी सरकारी नियंत्रण में है। लेकिन अब राज्य का जनमत बदल रहा है। बीजेपी की कोशिश तमिल हिंदुत्व को उभारकर अपनी बुनियाद को मजबूत करना है। वह डीएमके के इस दोहरे चरित्र को लोगों को समझाने की कोशिश में है। ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस बार गैर पारंपरिक रंग में नजर आ सकता है।

जीवन एक खाली कैनवास, हम इसमें रंग भरने वाले चित्रकार

जीवन एक अनोखा सफर है, जो हमें नए अनुभवों, नई चुनौतियों और नई संभावनाओं से भर देता है। यह एक ऐसा रंगमंच है, जहां हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन हमें अक्सर बताया जाता है कि जीवन का मकसद क्या है। दरअसल, जीवन का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। किसी को खूब पैसे कमाने होते हैं, तो किसी को खूब नाम कमाना होता है।

जीवन एक खाली कैनवास है और हम ही वह चित्रकार हैं, जो इसे रंगों से भर सकते हैं। यह एक मौका है, जब अपने लिए एक नया अर्थ, एक नया रास्ता बनाने के लिए अपनी कहानी के कैनवास में रंग भर सकते हैं। हम अपने सपनों को सच करने की हिम्मत कर सकते हैं, अपने डर को गले लगाकर उसे ताकत में बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जो समाज के बनाए बेबुनियाद नियमों से ऊपर उठता है, जो अपनी कमजोरियों को चुनौती देता है और अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को खोजता है, वही अपने सपनों तक पहुंच पाता है।

हम सबके भीतर वह शक्ति है कि हम सामान्य से असाधारण बन सकें, लेकिन इसके लिए हमें अपने डर, शक और समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ना होगा, जो हमें जकड़ती हैं। अपने आप को बार-बार नया बनाने और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने की जरूरत है। हर दिन खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं आज वह इंसान हूं जो कल था। दुख और पीड़ा से कोई नहीं बच सकता, लेकिन इनसे भागने की जरूरत नहीं है।

पीड़ा हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि गुरु है। हर दुख, असफलता, हमें कुछ सिखाती है। बल्कि जीवन में जब भी दुख आता है, तब वह एक तरह से व्यक्ति को मांजता है और जीवन के अगले अध्याय को बेहतर तरीके से जीने की राह खोजने की ओर प्रवृत्त करता है। दुख की अपेक्षा कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन सुख की महत्ता तभी समझ में आती है, जब दुख से गुजरना होता है।

जब जीवन नीचे गिराए, तो उठ कर और मुस्कराकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन एक नृत्य है, संगीत है, जिसे हमें अपने तरीके से जीना चाहिए। समाज हमें नियमों में बांधना चाहता है कि यह करो, वह मत करो, लेकिन यह वही वक्त होता है, जब हमें थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए और अपने दिल की सुननी चाहिए।

बस इतना जरूरी है कि हमारे दिल की बात के समांतर किसी और का दिल न दुखे या उसकी जिंदगी बाधित न हो। जीवन का आनंद उसकी आजादी में है, उसकी रचनात्मकता में है। यह आनंद अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ है। प्रेम, दोस्ती और रिश्ते, ये वे रंग हैं, जो हमारे जीवन को और खूबसूरत बनाते हैं।

प्रेम वह नहीं, जो हमें कमजोर बनाए। सच्चा प्रेम वह है, जो हमें और मजबूत बनाए, जो हमें हमारे असली स्वरूप को खोजने में मदद करे। अपने रिश्तों में ईमानदार रहा जाए और उन लोगों को चुना जाए, जो हमें ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचें। अपने कर्मों को इतना बड़ा करना चाहिए कि वे समय की सीमाओं को पार करें।

हमारा हर कदम, मेहनत, सपना हमें अमर बना सकता है। अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी कहानी दुनिया को प्रेरणा दे। अपने भीतर दया, करुणा और प्रेम मानवता के तीन महत्त्वपूर्ण पहलू को शामिल कर लेना चाहिए, जो हमारे जीवन को समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये गुण हमें दूसरों के साथ जुड़ने, उनकी जरूरतों और भावनाओं को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं।

जब हम दया, करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तो हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते है। ये गुण हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करते हैं।

जीवन एक चुनौती है, एक अवसर है, और सबसे बढ़कर, एक उपहार है। किसी भी स्थिति में इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। अपने भीतर जीने की आग को जलाए रख कर अपने तरीके से जीने की हिम्मत करने और अपने सपनों को सच करने की कोशिश करने की जरूरत है।

जीवन का आनंद उसकी आजादी में है, रचनात्मकता में है और दूसरों के साथ है। अगर हमारे भीतर एक सुखी और सफल जीवन जीने की भूख है, तो हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर रहना होगा। आत्मनिर्भरता एक सबसे महत्त्वपूर्ण गुण है, जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना और अपने निर्णय स्वयं लेना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। इसके कई लाभ हैं, जिनमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और आर्थिक स्थिरता शामिल हैं।

इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर निर्णय ले सकता है। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बेहतर निर्णय ले सके। आत्मनिर्भरता के लिए कुछ आवश्यक कौशल हैं, जिनमें निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, आत्म-प्रबंधन और संचार कौशल शामिल हैं। हमें अपने साथ संतुष्ट रहना सीखना होगा और अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और उनके लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान की बदहाली से उपजे खतरे, क्रिप्टोकरंसी के बहाने इस रणनीति पर हो रहा काम

आतंकवाद, हिंसा, अस्थिरता, संवैधानिक व्यवस्थाओं का अभाव, गरीबी और पिछड़ेपन से जूझते पाकिस्तान के कई इलाकों में आज भी बहुत सारी लड़कियों की स्कूल तक पहुंच नहीं है। अर्थव्यवस्था बेहाल है और गंभीर आर्थिक संकट है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लोग स्वास्थ्य सेवा सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय एजंसियों और मित्र देशों से उधार लिए गए पैसे पर चल रही है। पाकिस्तान की तीस फीसद से अधिक आबादी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में गंभीर अभाव से ग्रस्त है, जबकि लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही है।

महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझते इस देश के बारे में यह भी कहा जाता है कि कभी भी यहां बड़े नेताओं, सेना के परिवारों और अफसरों के लिए मंदी नहीं आती। इसका सबसे प्रमुख कारण नेताओं और सेना की अकूत संपत्ति है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोकरंसी को कवच बनाने की तैयारी हो गई है।

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता ने पूंजी के लिए असुरक्षित वातावरण बनाया है। ऐसे में जिनके पास साधन और संपर्क हैं, वे अपनी संपत्ति को देश में रखने के बजाय विदेश में सुरक्षित करना अधिक अच्छा मानते हैं। दूसरी ओर, वहां कर चोरी व्यापक समस्या रही है। जब राज्य स्वयं कर संग्रह में असफल रहता है और कानून का समान रूप से पालन नहीं होता, तब संपन्न वर्ग के लिए अपनी आय छिपाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।

यह छिपी हुई आय धीरे-धीरे विदेश में निवेश के रूप में बदल जाती है। परिणामस्वरूप, देश के भीतर विकास के लिए आवश्यक पूंजी बाहर चली जाती है। दूसरी ओर सरकार कर्ज और अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर होती जाती है।

पाकिस्तानी नागरिकों के पास दुबई में बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं, जिनका कुल मूल्य साढ़े बारह अरब अमेरिकी डालर है। दुनियाभर के कारोबारियों और नेताओं की गुप्त सौदेबाजी का खुलासा 2016 में हुआ था और इसके केंद्र में पाकिस्तान के कई नेता, उद्योगपति और सेना के अधिकारी थे।

बाद में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान की कुछ बड़ी हस्तियां गुपचुप तरीके से दौलत बाहर ले गईं। इस मामले में इमरान खान के कुछ सहयोगियों के नाम भी शामिल थे। काले धन को वैध बनाने, प्रतिबंधों से बचने और कर चोरी में मदद की वैश्विक कड़ियां जुड़ीं, तो पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मच गई और यह बड़ा मुद्दा भी बना।

नवाज शरीफ ने 2017 में पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बताया है, जहां सभी क्षेत्रों में यह बुराई व्याप्त है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रपट में सेना से जुड़े व्यवसायों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा समूह बताया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जून 2023 में देश को दिवालिया होने से बचाने में मदद करने के लिए सेना प्रमुख मुनीर को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया था। पाकिस्तानी सेना में जमीन हड़पने की लालसा इतनी अधिक है कि उनके जनरल सामंती जमींदारों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें जमीन माफिया कहा जाता है। यह एक ऐसा देश है जो आर्थिक संकट, कर्ज निर्भरता और मुद्रा अवमूल्यन से जूझ रहा है। क्रिप्टोकरंसी इस अविश्वास के वातावरण में राज्य-निरपेक्ष संपत्ति के रूप में सामने आती है। यह न किसी बैंक में रखी जाती है और न ही किसी एक देश के कानून के अधीन होती है। इसका नियंत्रण व्यक्ति के पास उसकी निजी डिजिटल कुंजी के माध्यम से रहता है। यही कारण है कि लोग इसे पूंजी सुरक्षा के एक साधन के रूप में देखते हैं। जब मुद्रा का तीव्र अवमूल्यन होता है या महंगाई बचत को निगलने लगती है, तब सीमित आपूर्ति वाली क्रिप्टोकरंसी लोगों को अपनी पूंजी के मूल्य को बचाए रखने का एक विकल्प प्रतीत होती है। सीमा पार पूंजी ले जाने के संदर्भ में भी क्रिप्टोकरंसी की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

पारंपरिक तरीकों में विदेशी मुद्रा नियम, सरकारी अनुमति, बैंकिंग प्रक्रिया और समय की लंबी देरी शामिल होती है। इसके विपरीत क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से व्यक्ति कुछ ही मिनटों में बिना किसी मध्यस्थ के दुनिया के किसी भी हिस्से में मूल्य का हस्तांतरण कर सकता है।

पाकिस्तान में क्रिप्टोकरंसी का मूल उद्देश्य आम नागरिकों को आर्थिक सशक्तीकरण देना नहीं, बल्कि राजनीतिक आभिजात्य और सैन्य प्रतिष्ठानों के धन को अंतरराष्ट्रीय निगरानी से सुरक्षित रखना प्रतीत होता है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और पश्चिमी वित्तीय एजंसियों की सख्त निगरानी है। ऐसे में क्रिप्टोकरंसी सत्ता वर्ग के लिए धन छिपाने, स्थानांतरित करने और प्रतिबंधों से बचने का एक वैकल्पिक माध्यम बन सकती है।

आम लोगों के लिए यह व्यवस्था लाभकारी नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी आर्थिक रूप से असुरक्षित है, वित्तीय साक्षरता कम है और डिजिटल ढांचे की पहुंच सीमित है। क्रिप्टो में निवेश उनके लिए जोखिम भरा है। न तो वहां मजबूत नियमन है, न उपभोक्ता संरक्षण और न ही किसी प्रकार की गारंटी। ऐसे माहौल में आम लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में अपनी जमा-पूंजी गंवा सकते हैं।

पाकिस्तान की लगभग पैंसठ फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका कृषि, पशुपालन, खेतों में मजदूरी और उससे जुड़े छोटे व्यवसायों पर निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था नकद लेन-देन, परंपरागत साहूकारी, आढ़ती प्रणाली और सीमित बैंकिंग तक ही सिमटी हुई है। डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच अब भी असमान और सीमित है। ऐसे में क्रिप्टोकरंसी जैसी जटिल, तकनीकी और अस्थिर वित्तीय व्यवस्था ग्रामीण पाकिस्तान के लिए लगभग अप्रासंगिक है।

ग्रामीण आबादी की प्राथमिक समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। जैसे बीज, खाद और डीजल की महंगाई, सिंचाई की कमी, जलवायु संकट, फसल का उचित मूल्य न मिलना, कर्ज का जाल और सरकारी सहायता का अभाव। क्रिप्टो इन समस्याओं का समाधान नहीं करता।

जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण जीवन, कृषि उत्पादन और स्थानीय बाजार हों, तब क्रिप्टोकरंसी विकास का इंजन नहीं बनतीं। पाकिस्तान के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि क्रिप्टोकरंसी न तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और न ही देश को आर्थिक स्थिरता देगी।

यह अधिकतर एक शहरी-आभिजात्य और सत्ता-संरक्षण परियोजना बन कर ही रह जाएगी, जिसका बोझ आखिरकार ग्रामीण और गरीब जनता पर पड़ेगा। अनियंत्रित पूंजी, क्रिप्टो और सट्टा अर्थव्यवस्था में असली उत्पादन की जगह वित्तीय जुगाड़ को समाधान समझा जा रहा है। क्रिप्टो को विकास का विकल्प बताना दरअसल यह स्वीकार करना है कि राज्य के पास संरचनात्मक सुधार की क्षमता नहीं बची।

जाहिर है, पाकिस्तान में क्रिप्टोकरंसी को बढ़ावा देना सुधार की नीति कम और सत्ता-संरक्षण की रणनीति अधिक दिखती है। इससे न तो आम जनता का जीवन सुधरेगा और न ही देश आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ेगा। वास्तविक लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पहले से शक्ति, सूचना और संसाधन मौजूद हैं, जबकि जोखिम का बोझ एक बार फिर आम नागरिकों पर ही पड़ेगा।

123वीं जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री को किया नमन

सपा कार्यालय में गोष्ठी कर किसानों के मसीहा के जीवन पर की गई चर्चा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व. चौधरी चरण सिंह के 123 वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। सपा के जिला कार्यालय जार्ज टाउन में आज उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर नमन किया गया।तत्पश्चात आयोजित गोष्ठी में सपा नेताओं ने उनके राजनैतिक सफरनामे की चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत, किसान एवं सामाजिक न्याय के मुद्दे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चरण सिंह की राजनीति के केंद्र में रहे।

जिलाध्यक्ष गंगापार अनिल यादव ने कहा कि चौधरी साहब ने देश के किसानों को उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए आवाज उठा कर किसानों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया बल्कि उनके उत्पाद के बिक्री की गारंटी भी दिलाई। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ़्तेख़ार हुसैन ने स्व चरण सिंह को सामाजिक न्याय का प्रबल पक्षधर बताया। कहा कि इमरजेंसीके बाद कांग्रेस के विरोधी खेमे में जनसंघ भी शामिल रहा लेकिन वैचारिक मतभेद के चलते आगे अलगाव हो गया जिसके चलते जनता पार्टी, लोकदल की नीव पड़ी। यमुनापार अध्यक्ष पप्पूलाल निषाद ने कहा कि चौधरी साहब कोसमाज का हर शोषित, पीड़ित वर्ग अपना नेता मानता रहा।

प्रवक्ता दान बहादुर मधुर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है। उनकी नीतियां किसानों, खेती, पशुपालन, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने वाली रही हैं। जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी जैसे कार्यक्रम भूमिहीनों, कमजोर वर्गों को राहत पहुँचाने वाली थी।

इस अवसर पर सर्व श्रीअनिल यादव, इफ़्तेख़ार हुसैन, पप्पू लाल निषाद, दान बहादुर मधुर, कृष्णमूर्ति सिंह, नरेन्द्र सिंह, श्रीमती कमला यादव, रावेन्द्र उर्फ़ रवि मिश्रा, महबूब उस्मानी, राम सुमेर पाल, मृत्युंजय पाण्डेय, विजय यादव, नाटे चौधरी, शांति प्रकाश पटेल, राम अवध पाल, दिनेश यादव, मो सऊद, के के यादव, विनय कुशवाहा, सचिन श्रीवास्तव, अशांजाळ, रूप नाथ यादव, विजय मुन्ना, मो जैद एडवोकेट, माधवनद चौरसिया आदि ने भी अपने विचार रखे।

टीजीटी, पीजीटी, टीईटी के लिए लाखों प्रतियोगियों को करना होगा इंतजार

आयोग पारदर्शिता के लिए इंटरनल विजिलेंस सिस्टम करेगा स्थापित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व डीजीपी डॉ प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोग की पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई। नव नियुक्त अध्यक्ष डॉ प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस दौरान चयन आयोग के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक विजिलेंस प्रणाली यानी इंटरनल विजिलेंस सिस्टम स्थापित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत आयोग में जल्द ही विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षा नियंत्रक से यह अपेक्षा की गई है कि बीते दिनों स्थगित टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के संबंध में परीक्षा तिथि निर्धारित करने के लिए अन्य आयोगों और भर्ती संस्थाओं के परीक्षा कैलेंडर का अध्ययन कर समय सारणी तैयार करें। अर्थात टीजीटी, पीजीटी और टीईटी के लाखों प्रतियोगी छात्रों को परीक्षा और नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा।

आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने वाली समय सारणी के आधार पर आयोग इन परीक्षाओं की तिथियों का भविष्य में निर्धारण करेगा। इसी के आधार पर आगामी परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों के चयन और विभिन्न प्रकार की एजेंसी के चयन आदि की कार्यवाही की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जल्द ही कैलेंडर जारी किया जाएगा, ताकि भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी और शुचिता के साथ संपन्न कराया जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि विज्ञापन संख्या- 51 की सहायक आचार्य यानि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के बाद लंबित इंटरव्यू के संबंध में लंबित बिंदुओं के परीक्षण के बाद जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की इस महत्वपूर्ण बैठक में अदालत के आदेशों के अनुपालन में अन्य प्रकरणों पर भी विचार विमर्श किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक मे लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी आयोग के उपसचिव और जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आज दी है।

पूस की सर्द रातों में भूरा मठ से निकली हमदर्दी की गर्मी

संगम की रेतीली धरती पर डूंग महाराज संस्थान में अन्नक्षेत्र का भी श्रीगणेश

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। शहंशाही नहीं, इंसानियत अदा कर मेरे मौला, मुझे लोगों पर नहीं दिलों पर राज करना है...। इन्हीं भावों को लेकर पूस की सर्द रातों में स्वामी डूंग महाराज संस्थान (भूरा मठ) के विद्यामार्तंड अरविंद स्वामी जोशी महराज निकल पड़े हैं। वह जरूरतमंद लोगों को हमदर्दी की गर्मी बांट वहां से ढेर सारी दुवा बटोरकर अगले पड़ाव पर चल देते हैं। विद्यामार्तंड अरविंद स्वामी जोशी बताते हैं कि वह मुंशी प्रेमचंद द्वारा वर्ष 1930 में रचित पूस की रात से काफी प्रभावित हैं। यह कहानी हल्कू नाम के किसान पर केंद्रित है। हल्कू को हांड़ कंपाने वाली ठंड में ऐसे कुत्ते के साथ सोना पड़ता था, जिसके शरीर से तेज दुर्गंध आती थी। वह मुफलिसी के ऐसे दौर से गुजर रहा होता था कि उसके पास दो जून की रोटी तक की व्यवस्था नहीं होती थी। दिल को झकझोरने वाली यह कहानी आज के समाज में काफी हद तक सच्चाई से सामना कराती है। ऐसे में अरविंद स्वामी अपनी टीम के साथ निःस्वार्थ भाव से न केवल गर्म कपड़े बांट रहे हैं बल्कि अन्नक्षेत्र का भी संचालन कर रहे हैं। मकसद केवल यह है कि कोई भी भूखा न सोने पाए। अरविंद स्वामी बताते हैं कि माघ महीने में वह संत समाज का भी सत्कार करेंगे। माघमेला स्थित भूरा मठ में 20 दिसम्बर से अन्नक्षेत्र शुरू हो गया है जो पूरे महीने चलेगा। अभी शिविर का निर्माण चल रहा है, फिर भी मेला क्षेत्र में कोई भूखा न सोये इसलिये अनवरत अन्न क्षेत्र शुरू हो गया है।

दबंगों ने फरसे से मारकर किशोर का सिर फोड़ा

मंत्र भारत संवाददाता

थरवई। थाना क्षेत्र के कुसुगुर गांव निवासी श्रवण कुमार (16) पुत्र पुरुषोत्तम लाल पर मंगलवार दोपहर गांव के दबंग युवकों ने किसी बात से नाराज होकर हमला कर दिया। आरोप है कि दबंगों ने किशोर को बेरहमी से पीटा और फरसे से वार कर उसके सिर में गंभीर चोट पहुंचाई।मारपीट की घटना में श्रवण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।घायल किशोर को पुलिस द्वारा इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शहर पश्चिमी से अधिवक्ता बीके सिंह राजू जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी घोषित

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। संगम नगरी की चर्चित विधानसभा जिस पर कभी बाहुबली अतीक अहमद और उसके बाद राजू पाल और अतीक अहमद के भाई अशरफ के बाद पूजा पाल का दबदबा था वही अब इस सीट पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह है और अब इस विधानसभा सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है सिविल लाइन स्थित रोजवुड रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता करते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के महानगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से बी के सिंह राजू प्रधान महासचिव जनसत्ता दल प्रयागराज को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यह निर्णय 21 दिसंबर 2025 को प्रयागराज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में पार्टी की नीतियों, संगठन विस्तार, आगामी चुनावी रणनीति तथा स्थानीय जनसमस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी पदाधिकारियों ने राजू सिंह के सामाजिक कार्यों, जनसंपर्क और संगठन के प्रति उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए उन्हें शहर पश्चिमी क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए जाने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई।

पार्टी नेतृत्व ने कहा कि राजू सिंह क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने में सक्षम हैं और उनके नेतृत्व में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रयागराज शहर पश्चिमी में संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगा। राजू सिंह को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने इसे आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बताते चलें वही प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भावी विधायक प्रत्याशी ने भी मौजूदा शहर पश्चिम से भाजपा विधायक पर बड़ा बयान देते हुए निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

मिशन शक्ति टीम द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक

प्रयागराज। पुलिस उपायुक्त यमुनानगर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे अभियान 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत जोन यमुनानगर कमिश्नरेट प्रयागराज की मिशन शक्ति टीम द्वारा बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को थाना क्षेत्र के स्कूलों/कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण तथा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे- सुकन्या समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना, चिकित्सा संबंधी आयुष्मान योजना व हेल्पलाइन नंबर जैसे- वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर 101 आदि के बारे में जानकारी दी गई, इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में जागरूक किया गया।

देहदान से अमर हुए मुन्नी लाल यादव, शिक्षा और श्रमजीवियों के लिए जीवन भर करते रहे संघर्ष

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के एनाटॉमी विभाग में संचालित देहदान अभियान के अंतर्गत एक अत्यंत प्रेरणादायक देहदान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2011 से चल रहे इस अभियान के तहत यह 108वां देहदान है, जो समाज में जागरूकता, वैज्ञानिक सोच और मानवीय सेवा की भावना को सशक्त करता है।

गंगोत्री हवेलिया, झूंसी निवासी 79 वर्षीय स्वर्गीय मुन्नी लाल यादव एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) डण्इ्घ(श). के सक्रिय सदस्य रहे और झूंसी स्थित लाल चौक के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकारों और गरीबों के हितों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और जमीनी स्तर पर

निरंतर सक्रिय रहे।

स्वर्गीय मुन्नी लाल यादव आज़ाद हिंद फ़ौज की वीरांगना कैप्टन डॉ. लक्ष्मी सहगल के देहदान से गहराई से प्रेरित थे। उसी प्रेरणा के चलते उन्होंने वर्ष 2012 में ही मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के देहदान अभियान के लिए अपना पंजीकरण करा दिया था। लंबी बीमारी के बाद 23 दिसंबर 2025 की रात अस्पताल में उनका निधन हो गया।

निधन की सूचना मिलते ही देहदान अभियान के संयोजक मनोज सैंगर द्वारा एनाटॉमी विभाग के आचार्य डॉ. बादल सिंह को अवगत कराया गया। विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णा तिवारी के निर्देशन में डॉक्टरों की एक टीम शव वाहन के साथ स्वर्गीय मुन्नी लाल यादव के निवास गंगोत्री हवेलिया, झूंसी पहुंची और पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज लाया गया।

मेडिकल कॉलेज में डॉ. कृष्णा तिवारी, डॉ. बादल सिंह, डॉ. निष्ठा सिंह, डॉ. ममता आनंद सहित सभी जूनियर डॉक्टरों एवं मेडिकल छात्रों ने विधिवत सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को स्वीकार किया। यह देहदान आने वाले वर्षों तक मेडिकल छात्रों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण में उपयोगी सिद्ध होगा। स्वर्गीय मुन्नी लाल यादव का देहदान समाज सेवा, वैज्ञानिक सोच और निस्वार्थ जीवन मूल्यों की एक उत्कृष्ट मिसाल है। उनके इस महान कार्य के प्रति पूरा मेडिकल कॉलेज परिवार कृतज्ञ है और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है।

वरिष्ठ समाजसेवी पंडित पारस नाथ द्विवेदी का निधन

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। वरिष्ठ समाजसेवी पंडित पारस नाथ द्विवेदी का निधन दिन मंगलवार दिनांक 23 जनवरी को उनके निवास राजापुर मल्हुआ, सोराम, प्रयागराज पर हो गया है। द्विवेदी ने मेवालाल अयोध्या प्रसाद इण्टर कालेज की स्थापना की और कई अन्य विद्यालयों में की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी अंतिम संस्कार रसूलाबाद घाट पर दिनांक 24 जनवरी को प्रातः 11 बजे किया जायेगा।

उक्त अवसर पर विद्यालय परिसर में एक शोक सभा आयोजित की गयी। शोक सभा को सम्बोधित करते हुए प्रवक्ता डॉ शैलेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि पारस नाथ द्विवेदी ने न केवल इस विद्यालय की नींव रखी, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे अनुशासन, सादगी और उच्च आदर्शों के प्रतिमूर्ति थे। उनके मार्गदर्शन में विद्यालय ने शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए।

पारसनाथ के निधन पर भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, प्रधानाचार्य अरविन्द कुमार सिंह, डॉ शैलेश कुमार पाण्डेय, डॉ रवीन्द्र प्रताप, गया प्रसाद, डॉ राम प्रताप, सुचेत शर्मा, वंदना सिंह, साधना, कविता त्रिपाठी, अमर सिंह, शैलेन्द्र पटेल, धर्मेंद्र सिंह, अजय पटेल, जगदीश प्रसाद शोक व्यक्त किया है।

टैगोर पब्लिक स्कूल का एक दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा दिवस कार्यक्रम सम्पन्न

वर्षा हाउस ओवरआल चैम्पियन

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। टैगोर पब्लिक स्कूल अतरसुईया, प्रयागराज के वार्षिक खेलकूद में 565 अंकों के साथ वर्षा हाउस ओवर आल चैम्पियन, 559 अंकों के साथ गीतांजली हाउस द्वितीय तथा 521अंकों के साथ लिपिका हाउस तृतीय स्थान पर रहा।बालिका वर्ग सीनियर में आराध्या केसरवानी, जूनियर वर्ग में नंदिता खन्ना तथा बालक वर्ग सीनियर में मो अब्दुल्ला तथा अक्षित यादव, जूनियर वर्ग सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए। वार्षिक क्रीड़ा दिवस के प्रथम सत्र का उद्घाटन सारस्वत खत्री पाठशाला के कोषाध्यक्ष तरूण मेहरोत्रा एवं द्वितीय सत्र का उद्घाटन उप्र लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य डॉ हरेश प्रताप सिंह ने किया। विशिष्ट अतिथि एमएमए फाइटर खुशबू निषाद उपस्थित रहीं।शुभारंभ हेड ब्वाय अनक चतुर्वेदी, हेड गर्ल अन्वेषा शर्मा, स्पोर्ट कैप्टन मीजान अहमद और काशवी शर्मा सहित चारों हाउस के प्रमुखों ने मशाल जलाकर किया।

मुख्य अतिथि उप्र लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य डॉ हरेश प्रताप सिंह ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक छात्र ऊर्जा से भरपूर होता है। वह अपने लिए निर्धारित उद्देश्य को स्वयं को सक्रिय रखकर प्राप्त कर सकता है जिसमें खेलकूद की भूमिका प्रमुख होती है। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया। इस अवसर पर सारस्वत खत्री पाठशाला सोसायटी की अध्यक्ष मीरा खन्ना, उपाध्यक्ष पूर्व न्यायमूर्ति अरुण टण्डन, टैगोर पब्लिक स्कूल समिति के प्रबन्धक अमित खन्ना, कोषाध्यक्ष पुनीत मेहरोत्रा, प्रधानाचार्या अर्चना तिवारी, समिति के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संगीता कपूर, दिव्या कपूर, ऊषा जायसवाल एवं नवनीत जायसवाल ने किया। धन्यवाद ज्ञापन क्रीड़ा अध्यापक विजय राय ने किया। इस अवसर पर आशीष कुमार, साधना मिश्रा, सौम्या सिंह एवं पूजा शर्मा मौजूद रहे। समापन राष्ट्रीय गान से किया गया।

इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद द्वारा 11 चलित दुकानों का वितरण आज

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 312 की जिला कॉन्फ्रेंस 'प्राजक्ता' के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक परियोजना के अंतर्गत 11 चलित दुकानों का वितरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम यशवंत विला में आयोजित होगा। चलित दुकानों का उद्घाटन एवं वितरण एसोसिएशन प्रेसिडेंट इनर व्हील 312, ज्योति महिपाल के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट 312 की जिला अध्यक्ष प्रिया नारायण की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। साथ ही इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद की प्रेसिडेंट नूपुर कपूर, सेक्रेटरी शालिनी अग्रवाल, एडिटर आरती अग्रवाल, आईएसओ नेहा कक्कड़, जोनल हेड तान्या ढल कोऑर्डिनेटर गीता चतुर्वेदी एवं क्लब की अनेक सदस्याएं कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगी। इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद की यह परियोजना स्वरोज़गार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय एवं प्रभावशाली पहल है, जिससे लाभार्थियों को सम्मानजनक आजीविका का अवसर प्राप्त होगा।

आर्य कन्या इंटर कालेज इंग्लिश मीडियम के वार्षिकोत्सव का समापन आज

वार्षिकोत्सव में दिखी बच्चों की प्रतिभा, बजती रही तालियां

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। आर्य कन्या इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम का दो दिवसीय वार्षिकोत्सव के पहले दिन आज वार्षिक क्रीड़ा दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधालय के प्रबंधक पंकज जायसवाल ने गुब्बारा उड़ाकर किया। इस दौरान छात्राओं ने मार्च पास्ट, दौड़ कबड्डी, खो खो तथा रिले दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सभी विद्यार्थियों ने अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर मनमोहन कृष्ण तथा जेडी फाईनेंस महेंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कॉलेज के प्रबंधक पंकज जायसवाल ने छात्र - छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ मधु सिंह ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। संचालन पारुल गुप्ता एवं सोनम जायसवाल ने किया। यह आयोजन छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत प्रेरणादायक सिद्ध हुआ।

भिवंडी में तीन साल बाद खत्म होगी प्रशासकीय शासन

2026 के पालिका चुनाव के बाद मिलेगा नया महापौर

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका में पिछले तीन वर्षों से जारी प्रशासकीय शासन का दौर अब समाप्ति की ओर है। वर्ष 2026 में होने वाले महापालिका के सार्वत्रिक चुनावों के बाद शहर को नया महापौर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही लगभग तीन वर्षों से खाली पड़ी महापौर की कुर्सी पर फिर से जनप्रतिनिधि का आधिकार स्थापित होगा। महापालिका चुनावों का बिगुल बज चुका है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बनी राजनीतिक दोस्तियां अब दरकिनार होती दिख रही हैं और नगरसेवक पद के इच्छुक उम्मीदवार 'मैत्रीपूर्ण मुकाबले' के नाम पर मैदान में उतरने लगे हैं। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही मनपा चुनावी रणभूमि में सियासी हलचल तेज हो गई है। शहर के जागरूक नागरिकों का मानना है कि निर्वाचित महापौर की वापसी से भिवंडी महापालिका प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त होगी और शहर के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलेगी। गौरतलब हो कि 16 दिसंबर 2001 को भिवंडी निजामपुर नगरपालिका को महानगरपालिका का दर्जा मिला था। इसके बाद मई 2002 में पहली बार महापालिका चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के सुरेश टावरे भिवंडी के पहले महापौर बने। उन्होंने 13 जून 2002 से 17 फरवरी 2005 तक पद संभाला। इसके बाद कोणार्क विकास आघाड़ी के विलास आर.पाटील (2005-2007), भिवंडी विकास मंच के जावेद गुलाम मोहम्मद दलवी (2007-2009), कोणार्क आघाड़ी की यशश्री राजन कडू (2009-2012) और फिर प्रतिभा विलास पाटील (2012-2014) ने महापौर पद की जिम्मेदारी निभाई। 11 दिसंबर 2014 से 8 जून 2017 तक शिवसेना के तुषार यशवंत चौधरी महापौर रहे। इसके बाद कांग्रेस के जावेद दलवी ने दोबारा 2017 से 2019 तक पद संभाला। फिर विलास आर.पाटील के नेतृत्व में प्रतिभा विलास आर. पाटील महापौर बनीं, लेकिन 8 जून 2022 को उनका कार्यकाल समाप्त होते ही महापालिका में प्रशासकीय शासन लागू हो गया। तब से लेकर अब तक महापालिका का कार्यभार आयुक्त प्रशासक के रूप में संभाल रहे हैं और महापौर पद रिक्त है।

करीब आठ साल बाद हो रहे इस महापालिका चुनाव में महापौर पद के लिए कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वार्ड स्तर पर प्रतिष्ठा की लड़ाई, आघाड़ियों में टूट-फूट और युतियों में खींचतान के संकेत मिलने लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इस बार स्थानीय समीकरण बड़े दलों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं।

कांग्रेस में टूट से बदली थी सत्ता :
भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका में महापौर और उपमहापौर पद के चुनाव के दौरान कांग्रेस के 18 नगरसेवकों के टूट जाने से भाजपा-कोणार्क विकास आघाड़ी की प्रतिभा पाटील महापौर चुनी गई थीं। वहीं उपमहापौर पद पर कोणार्क समर्थित कांग्रेस नगरसेवक इमरान खान निर्वाचित हुए थे। इससे कांग्रेस-शिवसेना गठबंधन को बड़ा झटका लगा था।

2017 चुनाव का गणितः
2017 के महापालिका चुनाव में 90 सीटों में से कांग्रेस को 47 सीटें मिली थीं और उसने शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता बनाई थी। भाजपा को 20, शिवसेना को 12, कोणार्क आघाड़ी व रिपब्लिकन पार्टी को 4-4, समाजवादी पार्टी को 2 और एक सीट निर्दलीय को मिली थी। हालांकि बाद में भाजपा-कोणार्क आघाड़ी ने कांग्रेस के 18 नगरसेवकों को तोड़कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

भिवंडी महापालिका निकाल 2017
कुल जागा -90
कॉंग्रेस- 47 विजयी
भाजप- 19 विजयी
शिवसेना-12 विजयी
कोणार्क विकास आघाडी -04 विजयी
समाजवादी -02 विजयी
आरपीआय (एकतावादी)
04 विजयी
राष्ट्रवादी-00
अपक्ष - 02

वर्तमान (2025) में पूर्व नगरसेवकों की स्थित :::
कॉंग्रेस- 25
भाजप- 21
शिवसेना शिंदे- 12
कोणार्क विकास आघाडी - 4
समाजवादी- 3
आरपीआय (एकतावादी)-4
राष्ट्रवादी शरद पवार गट - 20
भिवंडी विकास आघाडी मंच - 1
वर्ष 2022 से प्रशासक राजवट लागू है।

भिवंडी में राकांपा (अजीत गट) का एकला चलों,अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी.. महायुति में दिखने लगी दरार....

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। मनपा प्रशासन द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 16 जनवरी को मतगणना कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के तहत भिवंडी मनपा क्षेत्र में सात निर्वाचन केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर 23 दिसंबर, मंगलवार से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इसी बीच भिवंडी की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) ने भिवंडी मनपा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। राकांपा (अजीत गुट) के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने यह घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन के बिना चुनावी मैदान में उतरेगी। मंगलवार को आयोजित पत्रकार परिषद में प्रवीण पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि राकांपा (अजीत गुट) भिवंडी मनपा चुनाव में 34 से 40 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। उन्होंने कहा कि इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के पूर्व नगरसेवक भी शामिल होंगे। ऐसे इच्छुक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जल्द ही पार्टी में प्रवेश दिलाया जाएगा। प्रवीण पाटिल ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन में उनकी छवि, सामाजिक कार्यों में योगदान और जनता के बीच पकड़ को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को जमीनी स्तर पर अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और भिवंडी शहर में राकांपा एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। राकांपा (अजीत गुट) के इस फैसले के बाद भिवंडी में महायुति के भीतर मतभेद के संकेत मिलने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, अकेले चुनाव लड़ने के निर्णय से महायुति के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं, जिसका असर आगामी मनपा चुनाव के परिणामों पर भी पड़ सकता है,तीन वर्षों के प्रशासकीय शासन के बाद हो रहे भिवंडी मनपा चुनाव पहले से ही काफी अहम माने जा रहे हैं। ऐसे में राकांपा (अजीत गुट) का यह फैसला चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें नामांकन प्रक्रिया और आगामी राजनीतिक हलचलों पर टिकी हुई हैं।

भिवंडी मनपा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया तेज, पहले ही दिन 496 फॉर्मों की बिक्री

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद नामांकन फॉर्मों की बिक्री शुरू हो चुकी है। 23 दिसंबर 2025 को पहले ही दिन कुल 496 नामांकन फॉर्मों की बिक्री दर्ज की गई है, जबकि एक भी नामांकन दाखिल नहीं किया गया है।

मनपा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, भिवंडी मनपा क्षेत्र में सात निर्वाचन निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से नामांकन फॉर्मों की बिक्री की जा रही है। पहले दिन सबसे अधिक 133 नामांकन फॉर्म निर्वाचन निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 के कार्यालय से बेचे गए। आंकड़ों के अनुसार, निर्वाचन निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 के यहां 28, क्रमांक 2 के यहां 54, क्रमांक 3 के यहां 133, क्रमांक 4 के यहां 83, क्रमांक 5 के यहां 80, क्रमांक 6 के यहां 78 और क्रमांक 7 के यहां 40 नामांकन फॉर्मों की बिक्री हुई। सभी केंद्रों पर नामांकन फॉर्म दाखिल करने की संख्या शून्य रही।

मनपा चुनाव को लेकर शहर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों ने फॉर्म खरीदकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल नहीं किया है।

चुनाव विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आगामी दिनों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। जैसे-जैसे अंतिम तारीख नजदीक आएगी, उम्मीदवारों और समर्थकों की भीड़ नामांकन केंद्रों पर बढ़ने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि भिवंडी मनपा चुनाव को लेकर इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। कई पूर्व नगरसेवकों और नए चेहरों के मैदान में उतरने की चर्चा है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। मनपा प्रशासन ने सभी निर्वाचन केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी हैं और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए तैयारियों का दावा किया है।

सिर्फ ठाणे ही नहीं, 'चांदा से बांदा' तक शिंदे सेना की ताकत

भिवंडी मनपा की हांडी महायुति ही फोड़ेगी– उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विरोधियों पर तंज

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शिंदे सेना की ताकत सिर्फ ठाणे जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि 'चांदा से बांदा' तक फैली हुई है। नगरपंचायत और नगराध्यक्ष चुनावों के नतीजों के बाद यह बात विरोधियों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ऐसा व्यंग्यात्मक तंज उन्होंने भिवंडी में लगाया।शिंदे ने आगामी भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनावों को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार भिवंडी मनपा की 'हांडी' महायुति ही फोड़ेगी। उनके इस बयान से महायुति में शामिल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बना भ्रम भी दूर हो गया है

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना उपनेता रूपेश (दादा) म्हात्रे के भिवंडी के भादवड इलाके में नवनिर्मित जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने नगरपंचायत और नगराध्यक्ष चुनावों में विजयी हुए सभी उम्मीदवारों का अभिनंदन भी किया।

कार्यक्रम के दौरान भिवंडी-कल्याण मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर प्रभावित संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। यह मामला शिंदे के संज्ञान में आते ही उन्होंने अपने भाषण में प्रभावित नागरिकों को आश्वस्त किया कि रस्ता रुंदीकरण के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठाणे और डोंबिवली की तरह भिवंडी का भी विकास होना जरूरी है। शहरीकरण और विकास आवश्यक है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में जिनके घरों या दुकानों पर बुलडोजर चलेंगे, उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वसन दिया जाएगा।

भिवंडी मनपा चुनाव महायुति मिलकर लड़ेगी...

महापालिका चुनाव को लेकर लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर विराम लगाते हुए एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया कि आगामी मनपा चुनाव महायुति एकजुट होकर लड़ेगी। इससे यह साफ हो गया है कि भिवंडी मनपा की आने वाली सार्वत्रिक चुनावी लड़ाई महायुति पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरकर लड़ेगी।

आईआरसीटीसी वेस्ट जोन, मुंबई ने धूमधाम से मनाया 26वां एन्युअल डे समारोह

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी), वेस्ट जोन, मुंबई ने दिनांक 19/12/2025 को अपना 26वां एन्युअल डे समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया। इस अवसर पर श्री गौरव झा, ग्रुप जनरल मैनेजर, आईआरसीटीसी वेस्ट जोन ने पश्चिमी क्षेत्र की उल्लेखनीय उपलब्धियों की जानकारी साझा की।

अपने संबोधन में श्री झा ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष वेस्ट जोन के लिए दृढ़ता, निरंतरता और सशक्त प्रदर्शन का रहा है। चुनौतीपूर्ण एवं गतिशील कार्य वातावरण के बावजूद वेस्ट जोन ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए सराहनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

उन्होंने बताया कि मोबाइल केटरिंग, जो वेस्ट जोन का सबसे बड़ा राजस्व योगदानकर्ता है, ने वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग ?360 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। वेस्ट जोन द्वारा 13 वंदे भारत ट्रेनों, 12 राजधानी-शताब्दी ट्रेनों, 96 मेल/एक्सप्रेस WCB ट्रेनों, 83 एंड-टू-एंड TSV ट्रेनों तथा 329 ट्रेनों में सेक्शनल TSV मॉडल के अंतर्गत केटरिंग सेवाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

इसके अतिरिक्त, दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों–नागपुर-सिकंदराबाद तथा पुणे-कोल्हापुर–का भी सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया, जिससे यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सेवाएँ उपलब्ध हो सकीं।

इस वर्ष की एक प्रमुख उपलब्धि शॉर्ट-टर्म मोबाइल टेंडरों का लॉन्च-टर्म क्लस्टर मॉडल में सुचारु एवं सफल रूपांतरण रहा। वित्तीय वर्ष के दौरान 34 क्लस्टर, जिनमें 119 ट्रेनें और 163 किचन यूनिट्स शामिल हैं, का संचालन प्रारंभ किया गया।

इसके अलावा, चुनाव विशेष एवं FTR ट्रेनों में लगभग 7.56 लाख भोजन उपलब्ध कराए गए, जिससे लगभग ?14.20 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ, जो कि वेस्ट जोन के लिए गर्व की बात है।

इस अवसर पर आईआरसीटीसी पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई के ग्रुप जनरल मैनेजर गौरव झा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। कुल 50 कर्मचारियों को व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए, जिनमें भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के 11, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के 7 तथा नागपुर एवं भुसावल से दो-दो कर्मचारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, उत्कृष्ट सामूहिक योगदान के लिए 6 ग्रुप अवार्ड भी प्रदान किए गए।

झा ने कहा कि ये सभी उपलब्धियाँ आईआरसीटीसी वेस्ट जोन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पण, टीमवर्क और अथक परिश्रम का प्रतिफल हैं।

श्रद्धालुओं को अध्यात्म के साथ तीर्थ स्थल पर आने का आत्मिक संतोष प्राप्त हो-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नासिक जिले के मालसाने स्थित णमोकार तीर्थ के विकास हेतु ?36.35 करोड़ की विकास योजना को मंजूरी

मुंबई। नासिक जिले के मालसाणे (तालुका चांदवड) में स्थित जैन धर्मीयों के णमोकार तीर्थ के विकास के लिए 36 करोड़ 35 लाख की विकास योजना को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य इस प्रकार पूर्ण किए जाएं कि श्रद्धालुओं को यहां आने पर अध्यात्म के साथ-साथ तीर्थ स्थल पर आने का गहन आत्मिक संतोष प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि तीर्थ स्थल पर किए जाने वाले सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए और किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।

6 से 25 फरवरी 2026 के दौरान अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव का इस स्थान पर आयोजन किया जाएगा। कुल स्वीकृत राशि में से ?24.26 करोड़ स्थायी स्वरूप के विकास कार्यों पर तथा ?12.09 करोड़ महोत्सव आयोजन से संबंधित कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। बैठक में वित्त एवं योजना राज्यमंत्री एडवोकेट आशिष जयस्वाल तथा विधायक राहुल आहेर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि णमोकार तीर्थ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। संबंधित शासकीय यंत्रणाएं सभी आवश्यक सुविधाएं श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएं। देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आएंगे, इसलिए महोत्सव का आयोजन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक श्रद्धालु को यहां आने का पूर्ण संतोष प्राप्त हो। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी शासकीय यंत्रणाएं आपसी समन्वय से कार्य करें।

स्वच्छता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखने तथा जलापूर्ति योजनाओं के कार्य पूर्ण कर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिए।

णमोकार तीर्थ के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उसी दृष्टि से विकास योजना को लागू किया जाए। यह तीर्थ स्थल जैन समुदाय के लिए न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि देशभर में एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में उभरेगा। अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव के लिए देशभर से 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस महोत्सव को भव्य और सफल बनाने का आह्वान किया।

बैठक में नासिक के जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (लोक निर्माण) मनीषा म्हैसकर, सचिव (योजना) शैला ए, नासिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिला योजना अधिकारी विजय शिंदे तथा णमोकार तीर्थ के पदाधिकारी उपस्थित थे।

संक्षेप में: णमोकार तीर्थ विकास योजना णमोकार तीर्थ एक जैन धार्मिक स्थल है, जो नासिक-धुले महामार्ग पर मौजे मालसाणे गांव के पास 40 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। विकास योजना के अंतर्गत कंक्रीट सड़क निर्माण, संरक्षक दीवार, नौकायन सुविधाएं, हेलिपैड, पार्किंग व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति तथा स्वच्छता संबंधी कार्य किए जाएंगे।

6 से 25 फरवरी 2026 के दौरान आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्रतिष्ठान महोत्सव के लिए पानी की टंकियों की स्थापना, 450 यूनिट शौचालय ब्लॉक का निर्माण, विद्युतीकरण, सीसीटीवी व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष तथा अस्थायी चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा-राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

मुंबई। रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग नागरिकों को पारदर्शी और तेज़ सेवाएँ देने के लिए काम कर रहा है। इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा संबंधी और अन्य समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा, यह बात राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कही।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे, साथ ही संबंधित अधिकारी और एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक में रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सवालों और समस्याओं को सुना और विभाग के अधिकारियों को इन समस्याओं को हल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन और खाली पदों पर भर्ती के संबंध में तेज़ी से कार्रवाई की जानी चाहिए। सेवा प्रवेश नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के बाद फैसला लिया जाएगा। राजस्व विभाग की तर्ज पर स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के कर्मचारियों के पदनाम बदलने का प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए।

भारत एफआईएच विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर फिसला, महिला टीम 10वें स्थान पर

लुसाने (स्विट्जरलैंड) **(एजेंसी)**। भारत 2025 की शुरुआत पांचवें स्थान पर करने के बाद साल के अंत तक जाते-जाते एफआईएच विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर फिसल गया है जबकि महिला टीम 10वें स्थान पर है। 2025 में इंटरनेशनल हॉकी ने टॉप लेवल के एक्शन का एक लगातार कैलेंडर पेश किया - एफआईएच हॉकी प्रो लीग की लड़ाइयों से लेकर नेशंस कप और नेशंस कप 2 के रोमांच के साथ-साथ सभी महाद्वीपों में कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तक - जिससे एफआईएच वर्ल्डर् रैंकिंग में बड़े बदलाव हुए।

पुरुषों और महिलाओं दोनों के खेल में, जानी-मानी टीमों ने अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि उभरती हुई टीमों ने महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की। महिलाओं की रैंकिंग में, नीदरलैंड्स (3809) जिसने साल की शुरुआत टॉप स्थान पर की थी, उसने पूरे साल अपनी पकड़ बनाए रखी, एक और शानदार सीजन के साथ जिसमें उन्होंने प्रो लीग और यूरोहॉकी चैंपियनशिप में चैंपियनशिप जीतकर अपनी कैबिनेट में और ट्रॉफियां जोड़ीं, जबकि अर्जेंटीना उन्होंने साल की शुरुआत की थी।

स्पेन (2777) टॉप-10 रैंकिंग में साल के सबसे बड़े फायदे में रहने वालों में से है, क्योंकि वे पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि साल की शुरुआत आठवें स्थान पर की थी!

(3326), बेल्जियम (3109) और चीन (2977) ने शानदार कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और प्रो लीग अभियानों के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर बने रहे, जहां से स्पेन की यह बढ़त ऑस्ट्रेलिया (2758), जर्मनी (2734) और इंग्लैंड (2510) की कीमत पर हुई है, जो सभी एक-एक स्थान नीचे गिर गए हैं, और साल का अंत छठे, सातवें और आठवें स्थान पर किया है। न्यूजीलैंड (2319) जिसने 2025 में महिलाओं का एफआईएच हॉकी नेशंस कप और ओसनिया कप जीता था, वह भारत (2315) से ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गया है, जिसे 2025 में प्रो लीग से बाहर होना पड़ा था।

जापान (2186) और संयुक्त राज्य अमेरिका (2172) दो स्थान ऊपर चढ़कर ग्यारहवें और बारहवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि आयरलैंड (2030) और चिली (1999) तेरहवें और पंद्रहवें स्थान पर आ गए हैं, स्कॉटलैंड (2015) चौदहवें स्थान पर है। कोरिया (1864) सोलहवें स्थान पर बना हुआ है, उसके बाद फ्रांस (1742) है जिसकी एफआईएच हॉकी नेशंस कप 2 में जीत ने उसे तीन स्थान ऊपर चढ़ने में मदद की। इटली (1737), उरुग्वे (1736) और दक्षिण अफ्रीका (1670) टॉप-20 में शामिल हैं, जबकि कनाडा (1668) और मलेशिया (1667) बस थोड़ा ही पीछे हैं!

सुनील गावस्कर को मिली पर्सनैलिटी राइट्स की कानूनी सुरक्षा, बने पहले स्पोर्ट्सपर्सन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इतिहास रचते हुए पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की न्यायिक सुरक्षा पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस अहम फैसले ने न केवल खेल जगत बल्कि डिजिटल कानून और सेलिब्रिटी अधिकारों के क्षेत्र में भी एक नई मिसाल कायम की है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मशहूर हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनील गावस्कर के नाम, तस्वीर और पहचान के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी उल्लंघनकारी पोस्ट, वीडियो और संबंधित कंटेंट को 72 घंटे के भीतर हटाया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि संबंधित अकाउंट या यूजर ऐसा

करने में विफल रहते हैं, तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी होगी कि वे स्वयं ऐसे कंटेंट को हटाएं।

यह आदेश इसलिए ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि भारत में पहली बार किसी खिलाड़ी को उसके व्यक्तित्व और पब्लिसिटी अधिकारों के लिए स्पष्ट न्यायिक संरक्षण दिया गया है। खासतौर पर उन मामलों में, जहां बिना अनुमति किसी मशहूर खिलाड़ी के नाम और छवि का डिजिटल और व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा हो। यह फैसला भविष्य में खिलाड़ियों और खेल हस्तियों के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करेगा।

सुनील गावस्कर ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर बिना अनुमति उत्पाद बेचे जा रहे हैं और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट फैलाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इससे एक वरिष्ठ क्रिकेट कमेंटेटर और ब्रॉडकास्टर के रूप में उनकी साख को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि हास्य और व्यंग्य की आज़ादी अपनी जगह है, लेकिन ऐसा कंटेंट जो पहली नज़र में किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करे, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती।

गावस्कर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल जैन ने पक्ष रखा, जिन्हें क्रीडा लीगल की टीम ने ब्रीफ किया था। कोर्ट ने अश्लील और भ्रामक डिजिटल कंटेंट से जुड़ी चिंताओं को भी गंभीरता से लिया और साफ किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी तय करना बेहद ज़रूरी है।

भारत ने सेब, कीवी फल, शहद पर न्यूजीलैंड को शुल्क रियायतें कृषि योजनाओं से जोड़ी

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत न्यूजीलैंड को सेब, कीवी फल और मनुका शहद पर दी जाने वाली कोटा-आधारित शुल्क रियायतों को कृषि उत्पादकता वाली कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ दिया है जिनकी निगरानी 'संयुक्त कृषि उत्पादकता परिषद' (जेएपीसी) करेगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था बाजार पहुंच और घरेलू कृषि के संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।

इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत में सेब, कीवी और शहद क्षेत्रों की उत्पादकता, गुणवत्ता और क्षमताओं में सुधार के लिए लक्षित कार्ययोजनाओं पर सहमति जताई है। इस सहयोग के दायरे में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, बेहतर रोपण सामग्री की उपलब्धता, किसानों की क्षमता वृद्धि, बागवानी प्रबंधन में तकनीकी सहायता, कटाई के बाद की प्रक्रियाएं, आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य सुरक्षा से जुड़े उपाय शामिल हैं। बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले सेब के उत्पादकों के लिए विशेष परियोजनाओं और टिकाऊ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने से देश में उत्पादन और गुणवत्ता मानकों में सुधार की उम्मीद जताई गई है।

मंत्रालय ने कहा, 'सेब, कीवी फल और मनुका शहद से जुड़े सभी शुल्क दर कोटा कृषि उत्पादकता कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े होंगे और जेएपीसी इनकी निगरानी करेगी।' न्यूजीलैंड ने दावा किया है कि वह इस समझौते के तहत अपने सेब पर शुल्क रियायत पाने वाला 'पहला' देश बन गया है। फिलहाल भारत सेब के आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाता है। लेकिन इस एफटीए के तहत न्यूजीलैंड से आयातित सेब को एक तय कोटा और न्यूनतम आयात मूल्य के अधीन शुल्क रियायत दी जा रही है।

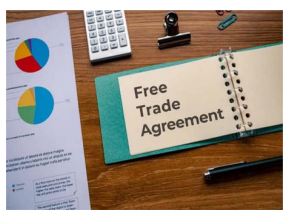

आंकड़ों के मुताबिक, न्यूजीलैंड से भारत में सेब का वार्षिक आयात 31, 392.6 टन है, जिसका मूल्य 3.24 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। यह भारत के कुल सेब आयात 5, 19, 651.8 टन (42.46 करोड़ डॉलर) का एक छोटा हिस्सा है। एफटीए के पहले वर्ष में न्यूजीलैंड को 32, 500 टन सेब पर शुल्क रियायत मिलेगी। यह कोटा छठे साल तक बढ़ाकर 45, 000 टन हो जाएगा जिस पर 25 प्रतिशत शुल्क और 1.25 डॉलर प्रति किलोग्राम का न्यूनतम आयात मूल्य लागू होगा। तय कोटे से अधिक आयात पर 50 प्रतिशत की दर से ही शुल्क लगेगा।

मर्सिडीज-बेंज इंडिया की 2026 में हर तिमाही में कीमतों में वृद्धि करने की योजना

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर ने मंगलवार को कहा कि कंपनी यूरो के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अगले कैलेंडर वर्ष में हर तिमाही में अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। कंपनी पहले ही एक जनवरी 2026 से अपने वाहनों की कीमतों में दो प्रतिशत तक की वृद्धि करने की योजना की घोषणा कर चुकी है। मूल्य समायोजन मौजूदा विदेशी मुद्रा चुनौतियों को दर्शाता है क्योंकि यूरो-रुपये की विनिमय दर 2025 में लगातार 100 रुपये के निशान से ऊपर बनी हुई है जो ऐतिहासिक औसत से काफी अधिक है। अय्यर ने यहां 'फिक्की मर्सिडीज-बेंज भारत इनोवेशन बिजनेस आइडिया चैलेंज प्रोग्राम' की शुरुआत के मौके पर 'पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में कहा, " हम अगले साल हर तिमाही में कीमतों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रहे हैं और इसका कारण यूरो के मुकाबले रुपये में गिरावट है।" उन्होंने बताया कि करीब 18 महीने पहले विनिमय मूल्य 89 रुपये प्रति यूरो था और अब यह लगभग 104-105 रुपये है। अय्यर ने कहा, " यह 15-18 प्रतिशत से अधिक की गिरावट है।" कंपनी ने हालांकि जनवरी से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन अय्यर ने कहा कि " भारी मूल्यह्रास की भरपाई के लिए " बाद में और भी बढ़ोतरी की जाएगी। अय्यर ने कहा कि रुपये में गिरावट और मूल्य वृद्धि के प्रभाव में 10-15 प्रतिशत से अधिक का अंतर है। उन्होंने कहा, " इसलिए हम मूल्य वृद्धि को धीरे-धीरे लागू कर रहे हैं, अन्यथा मांग भी प्रभावित हो सकती है।" अय्यर ने कहा कि हालांकि कंपनी ने 2026 की प्रत्येक तिमाही में अपेक्षित मूल्य वृद्धि की मात्रा को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है लेकिन यह प्रत्येक तिमाही में करीब दो प्रतिशत हो सकती है।

आंकड़ों के अनुमान को खराब मानने की मानसिकता को बदलने की जरूरत-सीईए

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने मंगलवार को कहा कि आंकड़ों का अनुमान लगाने के सभी तौर-तरीकों की कुछ सीमाएं होती हैं लेकिन भारत की जीडीपी का अनुमान लगाने की पद्धति को खराब मानने की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों को लेकर कुछ तबकों में जताई गई चिंताओं के बीच नागेश्वरन ने कहा कि चिंताएं तभी उठाई जाती हैं जब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े उम्मीद से कहीं अधिक होते हैं, जबकि आंकड़ों के निराशाजनक होने पर तौर-तरीकों पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, "ऐसा नहीं है कि भारत के जीडीपी के आंकड़े वास्तविक स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, ये सभी... अधूरी जानकारी वाले या अपूर्ण प्रश्न जानबूझकर लोगों के मन में संदेह पैदा करने के लिए अनुत्तरित छोड़ दिए जाते हैं। इससे कोई खास लाभ नहीं होता क्योंकि ये प्रश्न सावधानीपूर्वक और सटीकता के साथ नहीं उठाए जाते हैं।" उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित सीपीआई, जीडीपी और आईआईपी के आधार संशोधन पर परामर्श कार्यशाला में विभिन्न हितधारकों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

नागेश्वरन ने कहा, "सामान्य तौर पर, हम अनुमान लगाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और अनुमान लगाने के सभी तौर-तरीकों की अपनी सीमाएं होती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपनी पद्धतियों पर सवाल उठाने के बहुत शौकीन हैं और दूसरों की पद्धतियों पर कम। कहीं न कहीं इसके पीछे यह सोच है कि हमारे तौर-तरीके दूसरों से खराब हैं। यह हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है और इसे हमें बदलने की आवश्यकता है।" सीईए ने सरकार के आंकड़ों के अनुमानों की आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि आंकड़ों का मूल्यांकन करने, उन्हें सार्वजनिक करने या उनकी आलोचना लिखने के तरीके में सभी को अधिक परिपक्व होने की आवश्यकता है।

तेल के खेल में चीन बना नया 'किंग' कीमतों को खुद कर रहा कंट्रोल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। तेल की दुनिया में आमतौर पर माना जाता रहा है कि ओपेकऋजैसे बड़े तेल उत्पादक ही कीमतें तय करते हैं। वे उत्पादन घटाकर या बढ़ाकर बाजार में संतुलन बनाते हैं लेकिन साल 2025 में इस पुरानी सोच को चुनौती मिली। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन अपनी खरीद और भंडारण रणनीति से तेल की कीमतों के लिए 'फ्लोर' और 'सीलिंग' तय करने लगा।

ओपेकऋने अप्रैल 2025 में उत्पादन बढ़ाया लेकिन बढ़ी हुई कीमतें गिरने लगीं। इस अतिरिक्त तेल को खपाने और बाजार को स्थिर रखने की जिम्मेदारी चीन के पास आ गई। चीन अपनी स्ट्रैटेजिक और व्यावसायिक तेल भंडारण की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, जिससे यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि असल में कितना तेल बाजार में आ रहा है या जा रहा है।

साल 2025 के पहले 11 महीनों में चीन ने रोजाना लगभग 9.8 लाख बैरल अतिरिक्त तेल भंडारित किया। कुल आयात और घरेलू उत्पादन 15.80 मिलियन बैरल प्रति दिन था, जबकि रिफाइनरियों ने 14.82 मिलियन बैरल का इस्तेमाल किया। चीन का यह रणनीतिक खेल इस बात पर निर्भर करता है कि कीमतें गिरती हैं या बढ़ती हैं। जब कीमतें गिरती हैं, चीन ज्यादा खरीदता है और जब बढ़ती हैं, आयात कम कर देता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन इसी रणनीति के साथ भंडारण बढ़ाता रहा, तो साल 2026 में सप्लाई की अतिरिक्त मात्रा का बड़ा हिस्सा उसके टैंकों में जाएगा। इसका असर यह होगा कि तेल की कीमतों का न्यूनतम और अधिकतम स्तर चीन तय करेगा। कीमतें गिरने पर चीन खरीदेगा, कीमतें ज्यादा बढ़ीं तो आयात कम करेगा। इस तरह चीन तेल बाजार में ओपेकऋ के बराबर या उससे भी ज्यादा ताकत दिखा सकता है।

राशिद खान की बुलेटप्रूफ जिंदगी : अपने ही देश में बिना सुरक्षा नहीं घूम सकते स्टार क्रिकेटर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दुनिया के ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए शोहरत का मतलब होता है तालियां, लोकप्रियता और लग्ज़री लाइफ। लेकिन अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान के लिए यही शोहरत सुरक्षा खतरे भी साथ लेकर आती है। पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरसन के साथ बातचीत में राशिद ने अपनी ज़िंदगी की उस सच्चाई को उजागर किया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

बातचीत के दौरान जब पीटरसन ने राशिद से पूछा कि क्या वह काबुल की सड़कों पर सामान्य लोगों की तरह घूम सकते हैं, तो जवाब सीधा और चौंकाने वाला था– नहीं। राशिद ने बताया कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ कार का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह किसी शौक या रुतबे की बात नहीं, बल्कि जरूरत है। राशिद ने बेहद सामान्य लहजे में यह बात कही, जिससे साफ झलकता है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा चिंताएं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं।

राशिद खान सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय चेहरा हैं। आईपीएल, बीबीएल और अन्य टी20 लीगों में उनकी कामयाबी ने उन्हें वैश्विक पहचान, आर्थिक सफलता और प्रभाव दिलाया है। लेकिन यही पहचान उन्हें खतरे में भी डालती है। अस्थिर हालात वाले देश में मशहूर चेहरा और कथित संपन्नता किसी को भी आसान निशाना बना सकती है। राशिद जानते हैं कि जरा सी चूक गंभीर परिणाम ला सकती है।

जहां दूसरे देशों के खिलाड़ी बिना सुरक्षा के घूम सकते हैं, वहीं राशिद अपने ही वतन में यह आज़ादी नहीं पा सकते। न बेफिक्र सैर, न अचानक बाहर निकलने की सुविधा। बुलेटप्रूफ कार उनके लिए स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच है। खास बात यह है कि राशिद की बातों में न शिकायत है, न गुस्सा–बस सच्चाई की स्वीकारोक्ति। यही मानसिक मजबूती उन्हें मैदान के बाहर भी खास बनाती है।

राशिद की सुरक्षा चिंताओं की एक वजह उनका सामाजिक रुख भी है। उन्होंने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर खुलकर आवाज़ उठाई है। अपने अंतरराष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल कर वह सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि अंतरात्मा की आवाज़ बन चुके हैं। हालांकि, ऐसे मुद्दों पर बोलना एक अस्थिर माहौल में जोखिम भी बढ़ाता है, जिससे उनकी सुरक्षा और ज्यादा अहम हो जाती है। राशिद की कहानी और गहरी तब हो जाती है जब उनके बचपन की यादों पर नज़र डालें। एक समय ऐसा भी था जब बाहर निकलकर क्रिकेट खेलना तक सुरक्षित नहीं था। अफगानिस्तान के लिए खेलना किसी सपने से कम नहीं लगता था।

करेंसी मार्केट में आरबीआई की सख्ती, रुपए को थामने के लिए बेच डाले 11900000000 डॉलर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर 2025 में रुपए को सहारा देने के लिए करेंसी बाजार में आक्रामक हस्तक्षेप किया। आरबीआई ने इस महीने शुद्ध रूप से 11.9 अरब डॉलर की बिक्री की, जिससे यह साफ हो गया कि रुपए में स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय बैंक सबसे अहम भूमिका निभा रहा है।

आरबीआई के दिसंबर बुलेटिन के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 के दौरान केंद्रीय बैंक ने स्पॉट और फॉरवर्ड–दोनों बाजारों में सक्रिय रहकर रुपए में तेज उतार-चढ़ाव को रोकने की कोशिश की।

ओवर-द-काउंटर यानी स्पॉट मार्केट में अक्टूबर के दौरान आरबीआई ने डॉलर की खरीद से ज्यादा बिक्री की। डॉलर की कुल खरीद सितंबर के 2.2 अरब डॉलर से उछलकर 17.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई, जबकि बिक्री 192इ बढ़कर 29.6 अरब डॉलर हो गई। इसके चलते अक्टूबर में शुद्ध डॉलर बिक्री 11.9 अरब डॉलर रही, जो सितंबर के 7.9 अरब डॉलर से करीब 50इ अधिक है।

स्पॉट मार्केट के साथ-साथ आरबीआई ने भविष्य की उम्मीदों को नियंत्रित करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का भी इस्तेमाल किया। इससे तत्काल विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव नहीं पड़ा। अक्टूबर के अंत तक शुद्ध फॉरवर्ड बिक्री सितंबर के 59.4 अरब डॉलर से बढ़कर 63.6 अरब डॉलर हो गई। यह बड़ी फॉरवर्ड पोजीशन बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और जरूरत पड़ने पर डॉलर उपलब्ध कराने का भरोसा देती है।

एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स बाजार में आरबीआई ने अपनी शुद्ध पोजीशन न्यूट्रल रखी। अक्टूबर में केंद्रीय बैंक ने 2.3 अरब डॉलर खरीदे और उतने ही बेचे। हालांकि, ट्रेडिंग वॉल्यूम में तेज उछाल देखने को मिला और यह सितंबर की तुलना में 73.5इ बढ़ गया।

शिल्पा शेट्टी ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की जमकर तारीफ, सोशल मीडिया पर लिखा खास नोट!

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते में भी ज़बरदस्त कमाई कर रही है। तीसरे हफ़्ते में इसे जेम्स कैमरन की अवतारः फायर एंड ऐश से टक्कर मिली, फिर भी इसने भारत और विदेशों दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' के कलाकारों की जमकर सराहना करते हुए इसे "देशभक्ति" की भावना से लैस सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है। 'धुरंधर' पांच दिसंबर को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर. माधवन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म की कहानी कंधार विमान अपहरण, 2001 संसद हमला और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों जैसी भू-राजनीतिक तथा आतंकवादी घटनाओं की पृष्ठभूमि में खुफिया एजेंसियों के गुप्त अभियानों पर आधारित है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सोशल मीडिया मंच 'इंस्टाग्राम' पर सोमवार को एक वीडियो साझा किया जिसमें वह फिल्म के गीत 'एफ९एलए' के चर्चित 'स्टेप' (नृत्य) को करती नजर आ रही हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना पर फिलमाया गया यह 'स्टेप' काफी चर्चा में है।

उन्होंने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि रणवीर सिंह आपका समय आ गया हैष्ठ अभिनय सधा हुआ, बारीकियों से भरपूर था.. किरदार को पूरी तरह से निभाया। अक्षय खन्ना, जबरदस्त... मैडी (माधवन) आपसे बेहतर यह किरदार कोई नहीं निभा सकता था। अर्जुन रामपाल अप्रत्याशित रूप से शानदार ...संजय दत्त, हमेशा की तरह रॉकस्टार। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने फिल्म के अन्य कलाकारों गौरव गेरा, मानव गोहिल और राकेश बेदी के चयन के लिए 'कास्टिंग डायरेक्टर' मुकेश छाबड़ा की तारीफ की।

उन्होंने साथ ही लिखा, "...आदित्य धार आपने हाल ही में देशभक्ति की भावना से लैस सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनाई है। धुरंधर की पूरी टीम को सलाम।" फिल्म अभी तक वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है। आदित्य धर और उनके भाई लोकेश धर ने जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर अपनी निर्माण कंपनी 'बी62 स्टूडियोज' के बैनर तले 'धुरंधर' का निर्माण किया है। इसके अलावा धुरंधर ने हाल ही में कांतारा चैप्टर 1 (845.44 करोड़) को पीछे छोड़ दिया और दुनिया भर में 2025 की 1 भारतीय फिल्म बन गई। 18 दिनों में, रणवीर सिंह की फिल्म ने 900.10 करोड़ ग्रॉस कमाए हैं। इसमें घरेलू मार्केट में कमाए गए 706.70 करोड़ ग्रॉस शामिल हैं।

पिछले 24 घंटों में, इस स्पाई एक्शन थ्रिलर ने स्त्री 2 और बाहुबली 2 (हिंदी) के ग्लोबल लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। अब यह दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अब तक की 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। अगला टारगेट सीक्रेट सुपरस्टार को हराना है,

भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हराया, शेफाली का पचासा; सीरीज में 2-0 की बढ़त ली

विशाखापत्तनम। भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के नाबाद अर्धशतक की मदद से श्रीलंका को दूसरे टी20 मैच में सात विकेट से हराया। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को 20 ओवर में नौ विकेट पर 128 रन के स्कोर पर रोका। जवाब में भारत ने 11.5 ओवर में तीन विकेट पर 129 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत ने इस तरह पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों पर 11 चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 69 रन बनाए। वहीं, ऋचा घोष एक रन बनाकर नाबाद रहीं।

जेमिमा-शेफाली की शानदार साझेदारी

भारत के लिए शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत की, लेकिन ये साझेदारी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कविष्का ने मंधाना को आउट कर भारत को पहला झटका दिया जो 11 गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुईं। हालांकि, इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा ने शानदार साझेदारी की। जेमिमा और शेफाली ने आक्रामक बल्लेबाजी की जिससे भारत का स्कोर आठवें ओवर में ही 80 रन के पार पहुंच गया। काव्या कविंदी ने जेमिमा रोड्रिग्स को आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। जेमिमा हालांकि 15 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुईं जिससे इस साझेदारी का अंत हुआ। जेमिमा और शेफाली ने दूसरे विकेट के लिए 58 रन जोड़े। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुईं। श्रीलंका की ओर से माल्की मदारा, काव्या कविंदी और कविशा दिलहारी को एक-एक विकेट मिले।

श्रीलंका की खराब शुरुआत

पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत को एक बार फिर क्रांति गौड़ ने पहले ही ओवर में सफलता दिलाई। क्रांति ने विष्मी गुणारत्ने को आउट किया जो एक रन बनाकर पवेलियन लौटीं। श्रीलंका ने फिर 38 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया। स्नेह राणा ने कप्तान चामरी अट्टापट्टू को पवेलियन की राह दिखाई। चामरी 24 गेंदों पर तीन चौका और दो छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुईं।

श्री चरणी ने तोड़ी साझेदारी

हसिनी परेरा और हर्षिता समरविक्रमा ने शानदार साझेदारी कर श्रीलंकाई पारी को संभाला। भारत ने श्रीलंका को शुरुआती झटके दिए, लेकिन हसिनी और हर्षिता ने टीम को संभाला और दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी को श्री चरणी ने हसिनी को आउट कर तोड़ा जो 28 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 22 रन बनाकर आउट हुईं। इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहीं हर्षिता मदावी रन होकर पवेलियन लौट गईं। हर्षिता ने 32 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 33 रन बनाए। फिर पिछले मैच से डेब्यू करने वाली वैष्णवी शर्मा को आखिरकार टी20 करियर का पहला विकेट मिला। वैष्णवी ने निलाक्षी को आउट किया जो दो रन बनाकर आउट हुईं।

श्रीलंका ने आखिरी ओवर में गंवाए तीन विकेट

पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर श्रीलंका की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकी। टीम ने आखिरी ओवर में तीन विकेट गंवाए। श्रीलंकाई पारी का 20वां ओवर डालने वैष्णवी आईं। उन्होंने दूसरी गेंद पर शशिनी गिमहानी को आउट किया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर काव्या कविंदी रन आउट हुईं, जबकि अंतिम गेंद पर तेजी से दो रन चुराने के चक्कर में कौशानी भी अपना विकेट गंवा बैठीं। भारत के लिए वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी ने दो-दो विकेट लिए, जबकि क्रांति गौड़ और स्नेह राणा को एक-एक सफलता मिली।

राष्ट्रीय सम्मेलन में नदियों और जल निकायों को बहाल करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी का आह्वान किया गया

नई दिल्ली। नेचर केयर इनिशिएटिव (एनसीआई) द्वारा 'नदियों और जल निकायों के स्वास्थ्य को बहाल करना' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया।

मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए, राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि नदियों और जल निकायों का पुनरुद्धार केवल सरकारी कार्रवाई के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है। 'सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है,' उन्होंने कहा, पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार जीवनशैली के माध्यम से सार्थक परिवर्तन घरेलू स्तर पर शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'नागरिकों का हर छोटा प्रयास बड़े परिवर्तन में योगदान देता है।'

इन विचारों को दोहराते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर दीनबंधु साहू ने जोर देकर कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए सार्वजनिक भागीदारी अपरिहार्य है। गंगा-यमुना एक्शन प्लान में पर्याप्त निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि खर्च के

बावजूद नदियों को बहाल करने का काम अधूरा है। उन्होंने नागरिकों से इस मुद्दे को अपना मुद्दा मानने और समाधान खोजने में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। प्रोफेसर साहू ने दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण संकट के समाधान के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों की भी वकालत की।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील सौम्यजीत पाणि ने छोटे शहरों से लेकर महानगरीय शहरों तक शहरी परिदृश्य में सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन पत्रकार मंच के अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने प्रौद्योगिकी, नीति अभिसरण और निरंतर सार्वजनिक भागीदारी के मिश्रण के माध्यम से नदी बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया।

'नदियों और जल निकायों की सफाई में सामुदायिक भागीदारी' शीर्षक वाले एक तकनीकी सत्र में वाईएसएस फाउंडेशन के निदेशक सचिन गुप्ता; कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग की प्रमुख डॉ. संजुक्ता साहू; और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में सहायक प्रोफेसर डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने नागरिक नेतृत्व वाली पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की।

कार्यक्रम के दौरान, प्रो. दीनबंधु साहू को प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए नेचर केयर अवार्ड, 2025 से सम्मानित किया गया। नेचर केयर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, 2025, सचिन गुप्ता, डॉ. धर्मेंद्र कुमार और डॉ. संजुक्ता साहू को प्रदान किया गया।

जीआरएपी-4 हटने के बाद भी दिल्ली में जारी रहेगी बिना पीयूसी के ईंधन नहीं की नीति : मनजिंदर सिंह

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत, जीआरएपी-4 प्रतिबंध हटने के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी में 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण प्रदूषण परीक्षण केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और नए प्रदूषण नियंत्रण उपायों के साथ-साथ कड़ी जांच की जा रही है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में, जीआरएपी 4 के साथ-साथ, हमारा पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) अभियान 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नारे के साथ चल रहा था। जीआरएपी प्रतिबंध हटने के बाद भी हम इसे जारी रखेंगे। हमें अनियमितताओं में लिप्त 12 पीयूसी केंद्र मिले हैं, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।' औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, सिरसा ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने अब तक 411 बंद करने के नोटिस जारी किए हैं और दिल्ली नगर निगम ने 400 इकाइयों को सील कर दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चार नए स्वचालित परीक्षण केंद्रों को मंजूरी दी है। दिल्ली की ऊंची इमारतों की छतों पर लगे एएसजी (एंटी-स्मॉग गन) को संचालन के लिए अधिक समय दिया गया है और भवन मालिकों को अपने परिसर के आसपास मिस्टिंग सिस्टम लगाने का विकल्प दिया गया है। सिरसा ने बताया कि कैबिनेट ने होलंबी कलां में एक ई-कचरा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है और दिल्ली का पहला ई-कचरा संयंत्र जल्द ही स्थापित किया जाएगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 'गंभीर' हो गया है। शहर के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है। सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी चरण-4 के तहत सभी कार्रवाईयां लागू कर दी हैं।

प्रियंका को पीएम उम्मीदवार बनाने की माँग ने पकड़ा जोर राहुल गांधी की लगातार विफलता से परेशान हैं कांग्रेस नेता!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कांग्रेस में नेतृत्व और भविष्य की राजनीति को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पार्टी सांसद इमरान मसूद के उस बयान के बाद बहस ने जोर पकड़ लिया है जिसमें उन्होंने वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की वकालत की है। इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर और बाहर यह सवाल उठने लगा है कि क्या पार्टी राहुल गांधी के अलावा किसी नए चेहरे पर गंभीरता से विचार कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से यह मांग उठ रही है कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें स्वयं राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस समय सबसे जरूरी है जनता से जुड़े असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि व्यक्तियों के नामों पर बहस करना। इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा था कि यदि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो वह अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह सख्त जवाब देने में सक्षम होंगी। हम आपको बता दें कि इमरान मसूद यह टिप्पणी बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया का बचाव करते हुए कर रहे थे। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने अपने समय में पाकिस्तान को

ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है और प्रियंका गांधी उसी परंपरा की नेता हैं।

हम आपको बता दें कि कांग्रेस की परंपरागत राजनीति में अब तक राहुल गांधी को ही पार्टी का मुख्य चेहरा माना जाता रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति के मुकाबले। ऐसे में इमरान मसूद का बयान पार्टी की स्थापित लाइन से अलग नजर आया और इसने आंतरिक समीकरणों को लेकर अटकलों को हवा दे दी। हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर केंद्र सरकार से सख्त रुख अपनाने की मांग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपु चंद्र दास की भीड़ द्वारा की गई निर्मम हत्या बेहद चिंताजनक है और किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति या पहचान के आधार पर हिंसा मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए बांग्लादेश सरकार के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न मजबूती से उठाए।

देखा जाये तो यह पूरा प्रसंग कांग्रेस की राजनीति में छिपी बेचैनी और तलाश को उजागर करता है। एक ओर पार्टी औपचारिक रूप से राहुल गांधी को अपना नेता मानती है, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी का नाम बार बार उभरना यह संकेत देता है कि कांग्रेस अभी भी करिश्माई नेतृत्व की खोज में है। इमरान मसूद जैसे नेताओं के बयान यूं ही नहीं आते। वे पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मौजूद भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होते हैं।

देखा जाये तो प्रियंका गांधी की भाषा और तेवर में हाल के वर्षों में स्पष्ट आक्रामकता दिखी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा का मुद्दा उठाकर उन्होंने न केवल विदेश नीति से जुड़े मानवीय पहलू को छुआ बल्कि घरेलू राजनीति में भी सत्तारुढ़ दल को असहज करने की कोशिश की। यही वजह है कि उनके समर्थक उन्हें एक निर्णायक नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वहीं रॉबर्ट वाड्रा का यह स्वीकार करना कि प्रियंका के राजनीति में आने की मांग हर तरफ से उठ रही है, अपने आप में बहुत कुछ कह देता है।

बहरहाल, इस घटनाक्रम के राजनीतिक निहितार्थ दूरगामी हो सकते हैं। पहला, कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर बहस फिर सतह पर आ गई है। दूसरा, प्रियंका गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद से जोड़ा जाना उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक चेहरे के रूप में मजबूत करता है। यदि कांग्रेस आने वाले समय में प्रियंका गांधी को अधिक प्रमुख भूमिका देती है तो यह पार्टी की रणनीति में बड़ा बदलाव होगा। वहीं यदि पार्टी इस बहस को दबाने की कोशिश करती है तो असंतोष भीतर ही भीतर पकता रह सकता है।

बांग्लादेश का रणनीतिक यू-टर्न : पाकिस्तान से बढ़ाई सैन्य दोस्ती, भारत पर मंडराया परमाणु खतरा!

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। बांग्लादेश का भारत की खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक औपचारिक सैन्य समझौता करने की प्रक्रिया में है। यह समझौता उस मॉडल पर आधारित हो सकता है, जैसा पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब के साथ किया था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस प्रस्तावित करार में परमाणु सहयोग का पहलू भी छिपा हो सकता है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में तेज़ी से नज़दीकियां बढ़ी हैं, जबकि भारत के साथ संबंधों में ठंडापन आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका भारत से दूरी बनाते हुए इस्लामाबाद के और करीब जा रहा है, भले ही इससे आईएसआई को बांग्लादेश में कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देने का अवसर मिले।

भारतीय एजेंसियों के अनुसार, यदि यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग एक संस्थागत ढांचे में बदल जाएगा। इसके

तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करना और रणनीतिक समन्वय शामिल होगा। पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब को परमाणु क्षमता से जुड़ी 'संभावित छूट' का संकेत दे चुका है और अब ऐसी ही पेशकश बांग्लादेश को भी दिए जाने की आशंका है। पिछले आठ महीनों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। थलसेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी एक-दूसरे के देशों के दौरे कर चुके हैं। विशेष रूप से बांग्लादेशी सेना इस समझौते को लेकर काफी उत्साहित बताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, शुरुआत में योजना थी कि अंतिम समझौता फरवरी में होने वाले संसदीय चुनावों के बाद किया जाएगा, लेकिन अब इसे चुनाव से पहले ही अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यदि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (ँङ) सत्ता में आई तो यह समझौता अटक सकता है, क्योंकि ँङ हाल के महीनों में भारत के प्रति नरम रुख दिखा रही है। एक अधिकारी के अनुसार, यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर चुनाव टालने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि समझौते को लागू करने के लिए समय मिल सके। फिलहाल जनमत सर्वेक्षणों में ँङ को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन ढाका और इस्लामाबाद दोनों चुनावी रुझानों पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं।

अमेरिकी सांसदों का अलर्ट
चीन की सैन्य ताकत के पीछे टेक कंपनियों का खेल, पीएलए कनेक्शन उजागर

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक तनाव के बीच अमेरिका के नौ प्रभावशाली सांसदों ने चीन की कई तकनीकी कंपनियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इन सांसदों ने अमेरिकी युद्ध विभाग के सचिव पीट हेगसेथ को पत्र लिखकर मांग की है कि चीन की उन टेक कंपनियों को आधिकारिक सूची में शामिल किया जाए, जो कथित तौर पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की मदद कर रही हैं।

पत्र में कहा गया है कि ये गैर-सैन्य दिखने वाली टेक कंपनियां पीएलए की सैन्य आधुनिकीकरण, आंतरिक सुरक्षा अभियानों और सैन्य शक्ति के विस्तार में अहम भूमिका निभा रही हैं। गौरतलब है कि 2021 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत अमेरिकी रक्षा विभाग को ऐसी चीनी सैन्य संस्थाओं की सूची बनाए रखने का अधिकार दिया गया था, ताकि अमेरिकी सरकार अनजाने में सीसीपी की सैन्य या निगरानी गतिविधियों का समर्थन न करे। सांसदों ने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीपसीक का उल्लेख किया है।

कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत, उन्नाव रेप केस में मिली जमानत, उम्रकैद की सजा पर भी लगी रोक

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (23 दिसंबर) को उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के तीन जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने सेंगर को पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और न ही उसे या उसकी मां को धमकी देने का निर्देश दिया, और जमानत अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने को कहा। अदालत ने चेतावनी दी कि शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत ने कहा, 'किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।' सेंगर की सजा को दिसंबर 2019 में बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील के निपटारे तक निलंबित रखा गया है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर उच्च न्यायालय का फैसला आने तक जमानत प्रभावी रहेगी। यह मामला 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, इस मामले और संबंधित मामलों की सुनवाई 1 अगस्त, 2019 को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। सेंगर ने पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े एक अन्य मामले में भी अपनी सजा निलंबित करने के लिए अपील दायर की है, जिसमें उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। यह अपील फिलहाल उच्च न्यायालय में लंबित है।

जापान में बदल रही विदेशी श्रमिक नीति पुरानी ट्रेनिंग स्कीम खत्म, नई व्यवस्था होगी लागू

टोक्यो **(एजेंसी)**। जापान अपनी विदेशी श्रमिक नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2027 से शुरू होने वाले नए 'एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट' कार्यक्रम के तहत पहले दो वर्षों में अधिकतम 4, 26, 000 विदेशी कामगारों को ही अनुमति दी जाएगी। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब जापान को श्रम की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश में बढ़ते प्रवास को लेकर सार्वजनिक चिंता भी बढ़ रही है। क्योडो न्यूज के अनुसार, प्रधानमंत्री साने ताकाइची के निर्देश पर सरकार विदेशी कामगारों की नीतियों की समीक्षा कर रही है। इसमें वीज़ा अवधि समाप्त होने के बाद रुकने वालों पर सख्ती और निगरानी बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं। जापान में लंबे समय से लागू टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर सस्ते श्रम के शोषण और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप

लगते रहे हैं। इसकी जगह अब नया स्किल-आधारित ढांचा लाया जाएगा, जिसमें विदेशी कामगारों को तीन साल बाद स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर (एसएसडब्ल्यू) दर्जे में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

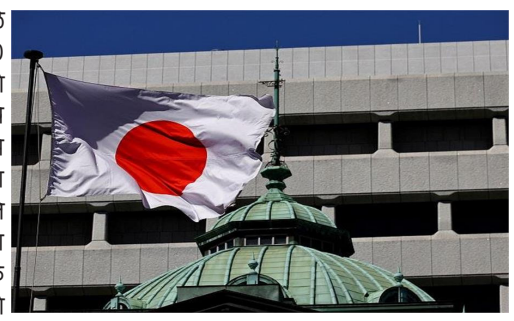

सरकारी मसौदे के मुताबिक, मार्च 2029 तक जापान लगभग 8.05 लाख विदेशी कामगारों को स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर योजना के तहत स्वीकार करेगा। यह संख्या मार्च 2024 में तय 8.20 लाख के लक्ष्य से थोड़ी कम है। सरकार का कहना है कि डिजिटल तकनीक और उत्पादकता बढ़ाकर इस कमी की भरपाई की जा सकती है।नई व्यवस्था के तहत कृषि और निर्माण सहित 17 सेक्टरों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल जापान में लगभग 3.33 लाख एसएसडब्ल्यू-1 वीज़ाधारी और 4.49 लाख तकनीकी प्रशिक्षु काम कर रहे हैं। कैबिनेट से इस योजना को जनवरी में अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है।

फोटोशूट बना मौत का खेल : समुद्र किनारे पोज दे रही लड़की को बहा ले गई लहर

काहिरा **(एजेंसी)**। मिस्र के समुद्र तट पर फोटोशूट के दौरान एक चीनी टूरिस्ट मॉडल के साथ हुआ हादसा सोशल मीडिया पर लोगों की सांसें थाम रहा है। खतरनाक चट्टान पर खड़ी होकर पोज दे रही मॉडल को अचानक पीछे से उठी विशाल समुद्री लहर बहा ले गई। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।न्यूयॉर्क पोस्ट और न्यूज़एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मर्सा मटरूह स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मटरूह आई पर हुई, जहां पर्यटक खूबसूरत चट्टानों और उफनती लहरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बताया गया कि इस इलाके में ज्वार-भाटा बेहद अप्रत्याशित रहता है और चट्टानों के पास खड़े लोगों के लिए यह बेहद खतरनाक हो सकता है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नारंगी रंग की पोशाक पहने मॉडल समुद्र की चट्टानों के बीच बने एक संकरे दर्रे में पोज दे रही थी। तभी अचानक तेज़ लहर उस दर्रे में घुस जाती है और मॉडल संतुलन खोकर नीचे समुद्र में गिर जाती है। लहरों के जोर से वह चट्टानों से टकराती है, जिससे उसके शरीर पर गंभीर खरोंच और चोटें आईं।हालांकि, इस हादसे में

मॉडल की जान बच गई।

महिला ने बताया कि वह पास में लगी सुरक्षा रस्सी को पकड़कर किसी तरह किनारे तक पहुंचने में सफल रही। सोशल मीडिया यूज़र्स का दावा है कि यह जीवनरक्षक रस्सी हाल ही में वहां लगाई गई थी, जिसने उसकी जान बचा ली। हादसे के बाद महिला ने कहा कि वह खुद को सौभाग्यशाली मानती है और भविष्य में यात्रा के दौरान ज्यादा सतर्क रहने का संकल्प लिया है। यह घटना एक बार फिर उन बढ़ती घटनाओं की याद दिलाती है, जहां खूबसूरत लेकिन खतरनाक जगहों पर फोटो खिंचवाने की चाह लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। विशेषज्ञों ने पर्यटकों से ऐसे स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)